

हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता ...

haryanamail.in @haryanamail

गुरुवार, 30 जुलाई, 2026

गुरुग्राम , वर्ष -14, अंक - 55, पृष्ठ-12, मूल्य : 3.00 रूपए
RNI NO. : HARHIN/2012/47672

बिल के नाम पर छात्रों को एक ... 12 Page

भोपाल में किसान आंदोलन उग्र, चार सुरक्षा घेरे तोड़ सीएम आवास की ओर बढ़े किसान

अन्नदाता की पुकार, सत्ता के गलियारों तक पहुंची

- ▶ राजधानी में किसान शक्ति का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरा अन्नदाता का आक्रोश
- ▶ हक की लड़ाई में किसान आर-पार के मूड में, सरकार पर बढ़ा दबाव
- ▶ 3 अगस्त तक मांगों नहीं मानी तो प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

हरियाणा मेल, एजेंसी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों का आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन उग्र हो गया। मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर रहे किसानों ने पुलिस की चार स्तरीय बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिससे कई स्थानों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

आंदोलन के दौरान कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर विरोध दर्ज कराया, जबकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ते रहे। सुरक्षा कार्रवाइयों से पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मूंग की शत-



किसानों की प्रमुख मांगें
मूंग की शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी। एमएसपी को कानूनी गारंटी। ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करना। खाद और कृषि संबंधी संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता। लंबित भुगतान और किसानों से जुड़े वादों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना।

प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और ई-टोकन व्यवस्था समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसान पिछले तीन दिनों से राजधानी में डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार लगातार आशवासन दे रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान

नहीं किया जा रहा।

किसानों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे, कांग्रेस कार्यालय, रेडक्रॉस अस्पताल और शिवाजी चौराहे के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया। कई स्थानों पर सड़क रोकने के लिए खड़ी बसों पर भी प्रदर्शनकारी चढ़ गए और उन्हें हटाने की कोशिश की। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया।

प्रदर्शन के दौरान कई किसानों ने अपनी कमजी और बिनियान उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रही, तब विरोध का यही रास्ता बचा है। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा और लगातार आर्थिक संकट

गहरा रहा है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास के बाहर आंदोलनकारी किसान पहुंचकर सड़क पर बैठ गए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने वाहनों को सड़क पर खड़ा कर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। मौके पर पुलिस का बम निरोधक (बॉम्ब डिस्पोजल) वाहन भी तैनात किया गया है। आवास के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारी दशरथ पटेल ने कहा कि किसान किसी से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने सरकार पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया। आंदोलन में शामिल कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मूंग की फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन में रायसेन से भोपाल पहुंची प्रियंका रघुवंशी ने सरकार से किसानों की मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगें पूरी नहीं करती है तो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए।

प्रदर्शन स्थल पर किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि हवन किया। वहीं कई किसान सड़क किनारे ही भोजन बनाते और आराम करते

आमजन पर असर, स्कूल बंद

किसान आंदोलन के कारण नर्मदापुरम रोड सहित कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने कई रास्तों पर बैरिकेडिंग कर ट्रैफिक जयवर्त किया, जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में लंबा जाम लगा। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्मदापुरम रोड स्थित सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। हजारों लोगों को कार्यालय, स्कूल और अस्पताल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

नजर आए। प्रदर्शन स्थल पर दाल-बाटी बनाकर सामूहिक भोजन की व्यवस्था भी की गई।

कांग्रेस का समर्थन
बुधवार शाम को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर किसान कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलनकारियों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी बनाया जाएगा। किसान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि 3 अगस्त तक मांगें पूरी नहीं होने पर हाईवे जाम और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा।

बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर उपचुनाव : सभी तैयारियां पूरी

मतदान आज, नतीजे ३ अगस्त को

- ▶ भाजपा-कांग्रेस समेत प्रमुख दलों की प्रतिष्ठा दांव पर

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग और संबन्धित प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए संवेदनशील केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल, अतिरिक्त पुलिस बल, वैबकार्टिंग, सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन और विक्क रिमॉस टीमों की तैनाती की गई है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी।



बिहार की बांकीपुर सीट भाजपा नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है। यहां 3.79 लाख से अधिक मतदाता 422 केंद्रों पर मतदान करेंगे। मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच माना जा रहा है। मध्य प्रदेश की दतिया सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई। यहां 2.20 लाख मतदाता 291 केंद्रों पर

मतदान करेंगे। 233 केंद्र संवेदनशील और 28 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है।

गुजरात की मांजलपुर सीट भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई है। यहां 2.19 लाख मतदाता 260 केंद्रों पर वोट डालेंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। तीनों सीटों के परिणाम 3 अगस्त को घोषित होंगे, जिन पर राजनीतिक दलों की नजर टिकी हुई है। उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा है। मतदान केंद्रों पर रैंप, पेनजल, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

पीओजेके में हिंसक प्रदर्शन, 20 लोगों की मौत का दावा

हरियाणा मेल, एजेंसी



श्रीनगर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में चुनाव बहिष्कार और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 20 लोगों की मौत और 33 से अधिक के घायल होने का खबर है। रावलकोट, मुजफ्फराबाद से सहित कई क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। संयुक्त अवामी एक्शन कमिटी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल किया गया। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं से मामले की स्वतंत्र जांच और जवाबदेही की मांग की है।

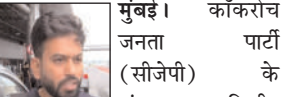
समाचार सार

भारत बाघ संरक्षण में

दुनिया का नंबर-1, देश में 3,682 बाघ

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में अपनी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को और मजबूत किया है। देश में अब दुनिया के लगभग 75 प्रतिशत बाघ मौजूद हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाघों की संख्या 3,682 तक पहुंच गई है, जो देश के 58 टाइगर रिजर्व में फैले हुए हैं। यादव ने अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बुधवार को एक्स पोस्ट में कहा कि बाघों की बढ़ती संख्या भारत के जंगलों की बेहतर स्थिति और वन्यजीव संरक्षण के प्रति लगातार किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि देश में संरक्षण संबंधी नीतियां और पहल प्रभावी रही हैं।

छात्रों को परेशान करना बंद करें, नहीं तो फिर आंदोलन होगा : दीपके



मुंबई। कांक्रोक जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर में कहा कि छात्रों को परेशान करना सरकार को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। अभिजीत दीपके दिल्ली में छात्र मुद्दों को लेकर हुए लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद आज अपने पैतृक शहर छत्रपति संभाजीनगर लौटे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में दीपके ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की मांग की।

पेपर लीक रोकथाम के लिए कानून को सख्त बनाने वाला विधेयक लोकसभा से पारित

- ▶ पेपर लीक कानून हुआ सख्त, सजा और जुर्माने में बढ़ोतरी

लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास, पारदर्शिता बढ़ाने का दावा

- ▶ विपक्ष पर राजनीति का आरोप, सरकार ने गिनाई उपलब्धियां

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। पेपर लीक से जुड़े मामलों में मौजूदा कानून को और सख्त बनाने वाला लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 बुधवार को लोकसभा में शोर-



शराबे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को उम्मीद थी कि इस विषय पर सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। डॉ. सिंह ने कहा कि जनवरी 2024 में लागू किए गए कानून को हाल की घटनाओं और विरोधों की

सलाह के आधार पर और प्रभावी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि नए संशोधन में कदाचार करने वालों की सजा तीन से पांच वर्ष से बढ़ाकर पांच से दस वर्ष कर दी गई है। साथ ही जुमाना बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया गया है। परीक्षा संचालक संस्थाओं पर अधिकतम जुर्माना एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया गया है और उन्हें आठ साल तक परीक्षा संचालन से रोक जा सकेगा। संगठित अपराध के मामलों में न्यूनतम सजा सात वर्ष और जुमाना 10 करोड़ रुपये तक करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कहना गलत है कि 2024 के कानून के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दो वर्षों में इस कानून के तहत 52 एफआईआर दर्ज की गई

नेता प्रतिपक्ष के रूप में विफल रहे राहुल गांधी: किरेन रिजिजू

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के रवैये से वह दो कारणों से बेहद नाराज हैं।

रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक पर एक भी ठोस बिंदु नहीं रख सके। मकर द्वार पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि

इसके बजाय राहुल गांधी ने अर्सेसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और गृह मंत्री पर गलत आरोप लगाए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री या कोई अन्य मंत्री किसी पर गोली चलाने का आदेश नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के आदेश संबंधित स्थान पर मौजूद मजिस्ट्रेट या एसडीएम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को इस बुनियादी प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने ही बयान से खुद को मुश्किल स्थिति में डाल लिया है।



बैठक

विकसित भारत विजन-2047 को लेकर सीएम ने लिया फीडबैक

सीईटी पास युवाओं को नवंबर से मिलेगा मानदेय: नायब सैनी

- ▶ प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना में हरियाणा को टॉप टेन में मिला स्थान: मुख्यमंत्री
- ▶ फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का बनेगा रिजिनल सेंटर

हरियाणा मेल ब्यूरो



2047 के तहत रोजगार, रिकल डिवलेपमेंट एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग एवं हरियाणा रिकल डिवलेपमेंट मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय रिकल प्रतियोगिता में राज्य के 5 युवाओं का चयन किया गया है। सितम्बर माह के दौरान चीन में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं जाँच सुनिश्चित की जाएगी।

तीसरे माह बैठक आयोजित कर आईटीआई एवं रिकल डिवलेपमेंट कार्यों की समीक्षा की जाएगी ताकि इन योजनाओं को जल्द मुर्तपुर् देकर युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। पंचकुला व गुरुग्राम में एआई हब बनाया जा रहा है। युवाओं को एआई के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक किया जाएगा तथा 2 लाख युवाओं को हार्ड रिकल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नवीनीकरण किया जाएगा तथा फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का रिजिनल सेंटर बनाया जाएगा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का

सर्वे करवाया जाए जिसमें विशेषकर तकनीकी रूप से युक्त युवाओं की अलग से पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से निपुण करने के लिए आईटीआई में नए कोर्स शुरू किए जाएं जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के योग्य बनाया जा सके और उद्योगों के अनुरूप निपुण युवा उपलब्ध हो सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईटी पास युवाओं को 100 घण्टे का काम दिया जाएगा। दो साल तक रोजगार न मिलने पर सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। सर्वे के दौरान 5 लाख 40 हजार 428 सीईटी पास युवा पाए गए हैं। इन युवाओं को एक नवम्बर से योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए नए प्रशिक्षण आरम्भ करने के लिए हर जिले में मॉडल आईटीआई

खोलने की योजना है। इसके अलावा हर ब्लॉक स्तर पर भी आईटीआई खोली जाएगी। प्रदेश के 143 ब्लॉक में से 117 ब्लॉकों में आईटीआई कार्यरत हैं। इसके अलावा सरकारी दादरी के झोड़ू कला, कारीरूपा व रणकोली तथा पिल्लू खेड़ा में नई आईटीआई खोली जाएगी। इसके अलावा नरनौल में महिला आईटीआई का नवीनीकरण किया जा रहा है। पंचकुला के बरवाला, कुरुक्षेत्र के वसंतपुर, तथा नलवां खुर्द में भी आईटीआई का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को एआई रोबोटिक, ड्रोन ऑपि का प्रशिक्षण देने में केन्द्र बनाए जा रहे हैं। इन केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए आधुनिक स्तर की मशीनें उपलब्ध कराई जाएगी। इनके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है।

धर्म-जाति राजनीति पर सरकार घिरी

प्रचार नहीं, शिक्षा और रोजगार बनें मुख्य मुद्दा: मीत हेयर

- ▶ दोषियों को पहले ही सजा नहीं मिल रही, केवल सजा बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

हरियाणा मेल, एजेंसी



चंडीगढ़। संग्ररू से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर ने लोकसभा में जन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए युवाओं के संघर्ष की सरहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की ताकत ने 12 वर्षों से धर्म और जाति की राजनीति करने वाली सरकार को आईना दिखाया है। अब प्रचार की बजाय शिक्षा और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दे मुख्यधारा में आ गए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आधी रात को सेल्फी वीडियो जारी करना सरकार की घबराहट दर्शाता है। जंतर-मंतर आंदोलन ने सरकार की नीतियों और नफरत की राजनीति को उजागर किया है। मीत हेयर ने कहा कि नए विधेयक में केवल सजा बढ़ाने की बात है, जबकि 2024 से अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली, इसलिए इससे वास्तविक बदलाव नहीं आएगा।

लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर दो बार हंगामा, अमित शाह पर आरोप से सत्ता पक्ष भड़का

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर दो बार हंगामा हुआ। पहली बार तब जब उन्होंने इंडियट और अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल किया और दूसरी बार तब जब उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों पर पैलेट गन इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। दोनों ही मौकों पर सत्ता पक्ष ने कड़ा हंगामा जताया और सदन में शोर-शराबा हुआ।

राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ छात्राओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए की। एक युवा लड़की ने उनसे कहा कि विद्यार्थी वह होता है जिसका मन और दिल खुला हो। उसने कहा कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, वे खुद को भगवान मानते हैं और दूसरों की सच्चाई का सम्मान नहीं करी। जब उन्होंने पूछा कि ऐसे लोगों को वह क्या कहती है तो



लड़की ने जवाब दिया मैं उन्हें इंडियट कहती हूं। संसदीय कार्यमंत्री किरन रिजिजू ने इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की। स्पीकर ओम बिरला ने यह शब्द सदन की कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि यह गुस्सा या नफरत नहीं था बल्कि देश के युवाओं और आने वाली पीढ़ी की गहरी भावना का इजहार था। छात्रों का सम्मान होना चाहिए और भाजपा नेताओं को यह समझना चाहिए कि यही युवा देश के भविष्य हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नेता अपने बच्चों से पूछें तो वे भी

छात्रों के समर्थन में खड़े होंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल पर हुआ। इस आरोप पर सत्ता पक्ष ने फिर हंगामा किया। किरन रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात रखने दी जाए लेकिन असंसदीय शब्द रिकॉर्ड से हटाए जाएं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों को भारत में अपनी बात कहने और सवाल पूछने की आजादी

नहीं दी जा रही है। उन्हें मनगढ़ंत हिस्ट्री मानने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था निजीकरण और वसूली से भरी हुई है।

सदन में हंगामे के बीच राहुल गांधी ने कहा कि जब भी वह बोलते हैं सत्ता पक्ष शोर मचाते लगता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को छात्रों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यही युवा देश का भविष्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जो हुआ है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को नसीहत दी कि बिना तथ्यों के किसी पर आरोप न लगाएं। इस दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष केवल आरोप लगा रहा है।

संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे के कारण बाधित हो रहा है। बुधवार को भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और विपक्ष की नारेबाजी के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा।

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में हंगामा



नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर चर्चा और जवाबदेही की मांग की, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक फिर प्रश्नकाल शुरू होते ही हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने हंगामे के बीच कहा कि देश में लोग सुरक्षित नहीं हैं और लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस बर्बरता पर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की।

खरगे के बयान का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल किसी भी छात्र कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, मैं भी छात्र जीवन में गिरफ्तार हुआ था। आपातकाल के दौरान जेल गया था। आंदोलन करने वाला हर छात्र कार्यकर्ता जानता है कि ऐसे आंदोलनों में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं।

इस दौरान राज्यसभा के सभापति ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे।

राज्यसभा में कुछ सदस्यों के बोलने के बाद लगातार जारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यौन उत्पीड़न मामले में ट्रेनी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार

हरियाणा मेल, एजेंसी



हैदराबाद। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की एक साथी ट्रेनी भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी द्वारा दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में अट्ठपुुर पुलिस ने बुधवार को आरोपित ट्रेनी आईपीएस अधिकारी उदय कृष्णा रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत दर्ज होने के लगभग दस दिन बाद हुई इस गिरफ्तारी को मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उदय कृष्णा रेड्डी का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसे अस्पतािया जनरल अस्पताल भेजा। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड के लिए राजेंद्रनगर स्थित अदालत में पेश किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब हाल ही में मीडिया में यह खबर सामने आई थी कि उदय कृष्णा रेड्डी ने कथित रूप से आत्महत्या का प्रयास किया था। उन्हें एमआर नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह मामला

कर्नाटक के डर की 30 वर्षीय विवाहित ट्रेनी आईपीएस अधिकारी द्वारा 18 जुलाई को दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उदय कृष्णा रेड्डी ने उनके साथ लगातार यौन उत्पीड़न किया और कई बार शारीरिक हिंसा भी की। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपित ने उन्हें अशोभनीय संदेश भेजे, जबरन एक कमरे में ले गया, बाल खींचकर मारपीट की, गला घोटने का प्रयास किया और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने उनकी जानकारी के बिना एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे उनके पति को भेजकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इन आरोपों के आधार पर अट्ठपुुर पुलिस ने

अमेरिकी और सऊदी सेना के हमले में कम से कम 20 इराकी लड़के मारे गए



हरियाणा मेल, एजेंसी

बगदाद। अमेरिका और सऊदी अरब की सेना ने इराक में पाँपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) पर हमला किया है। इस हमले में पीएमएफ के 20 लड़के मारे गए हैं। इस फोर्सेज को ईरान का समर्थन प्राप्त है। यह एकीकृत सैन्य कार्रवाई पिछले 30 दिनों में सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हुए ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि एकीकृत सैन्य कार्रवाई से पहले ईरान ने जॉर्डन में उसके एक बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएफ ने बयान में स्वीकार किया है कि यह हमले सात प्रांतों में किए गए। अमेरिकी-सऊदी सेना के संयुक्त हमलों में उसके कम से कम 20 लड़के मारे गए और 32 अन्य घायल हो गए। पीएमएफ ने कहा कि हताहतों की यह संख्या शुरूआती है। इसमें बंदोतरी हो सकती है। शुरूआती खबरों में दावा किया गया था कि हमले के बाद इराक के उत्तरी निनवेह प्रांत और दक्षिणी बसरा

प्रांत में कई स्थानों में आग लग गई। पीएमएफ ने सुबह स्वीकार किया था कि निनवेह में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं।

पाँपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज इराक का आधिकारिक सरकारी सुरक्षा बल है। इसकी स्थापना 15 जून 2014 को ईरान समर्थित शिया मिलिशिया समूहों को मिलाकर की गई थी। कहने को तो यह पीएमएफ इराकी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में काम करता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से इस पर ईरान का गहरा प्रभाव माना जाता है। संगठन के बयान में कहा गया कि इन हमलों में बगदाद, वासित, निनवे, बसरा, किरकुक, कर्बला और दियाला प्रांतों में पीएमएफ के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों से इमारतों, गाड़ियों और सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा है।

यमन के ईरान समर्थित आतंकी समूह हूती ने पीएमएफ पर हमले की निंदा की है। हूती ने अल-मसोराह टीवी पर जारी बयान में कहा कि यह इराक की संप्रभुता पर खुला हमला है। इस बीच खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) ने पूर्व में ईरान समर्थित समूहों के सऊदी अरब पर किए गए हमलों की निंदा की है। जीसीसी महासचिव जसमी मोहम्मद अल-बुदेई ने कहा कि इराक का ईरान समर्थक मिलिशिया पिछले कुछ समय से सऊदी अरब पर आतंकवादियों की तरह हमले कर रहा है। यह सऊदी अरब की संप्रभुता पर सीधा हमला है। सनद रहे खाड़ी सहयोग परिषद सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। अल-बुदेई ने कहा कि जीसीसी देश सऊदी अरब के साथ खड़े हैं।

पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम

कानून का संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब के प्रभारी को सौंपा



अमृतसर। पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम कानून के विवादित प्रावधानों में संशोधन करके नया मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब को सौंप दिया है। विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर और डिप्टी कमिश्नर

दलविंदरजीत सिंह ने सरकार का पक्ष और संशोधित ड्राफ्ट श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के प्रभारी बगोया सिंह को सौंपा। मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. इंदबीर सिंह निज्जर ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के और से कानून पर उठाई गई सभी प्रमुख आपत्तियों को संशोधित मसौदे में दूर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब यह मसौदा अध्ययन के लिए श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय के पास है और वहां से मिलने वाले सुझावों या निर्णय के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डॉ. निज्जर ने बताया कि दस्तावेज सौंप जाने के समय जयधर साहिब मौजूद नहीं थे।

इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब ने कानून के प्रारूप पर छह प्रमुख आपत्तियां जताई थीं। इनमें बौद्ध की जगह सरूप शब्द के प्रयोग, कस्टोडियन संबंधी प्रावधान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूपों को यूनिक नंबर देने की व्यवस्था, कस्टोडियन की जिम्मेदारियां तय करने, सजा संबंधी प्रावधानों की स्पष्टता तथा दुर्घटना की स्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सरूप को केस प्रॉपर्टी न बनाए जाने संबंधी प्रावधान शामिल थे।

खबरें फटाफट

पंजाब की अदालत से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट

चंडीगढ़। पंजाब में संगरूर की जिला अदालत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ वारंट जारी किया है। उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।

खरगे के वकील एडवोकेट ललित गर्ग ने बताया कि यह मामला 2023 का है, जब संगरूर निवासी हितेश भारद्वाज (बजरंग दल सदस्य) ने खरगे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। खरगे पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बजरंग दल की तुलना पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन पीपूल्स आर्मी से की थी और कहा था कि सत्ता में आने पर वे इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देंगे। पहले यह मामला सिविल प्रकृति का था, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे के वकील पेश हुए थे। अब कोर्ट ने इसे आचार्यिक मामला बना दिया है। यदि खरगे इस मामले में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है।

नोएडा सीवेज प्लांट हादसे पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की एक आवासीय सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जहरीली गैस से दो लोगों की मौत के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली कि 26 जुलाई को सफाईकर्मिैं टैंक की सफाई के लिए अंदर गया और बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड भी अंदर गया लेकिन वह भी बेहोश हो गया। दोनों को पुलिस और दमकलकर्मियों ने बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर रूस ने लगाया आतंकवाद में मदद का आरोप

माँस्को। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) ने मैसैजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोव पर आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय वांटेड सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एफएसबी द्वारा जारी बयान में कहा गया कि पावेल डुरोव के खिलाफ रूसी आचार्यिक संहिता की धारा 205.1 (याग 1.1) के तहत आतंकवादी गतिविधियों में मदद करने के आरोप ने आचार्यिक जांच चल रही है। रूसी एजेंसी का आरोप है कि टेलीग्राम ने रूसी कानूनों का उल्लंघन करते हुए ऐसे कई चैनलों, चैट और बॉट्स को नहीं हटाया, जिनका कथित तौर पर यूक्रेनी विशेष सेवाओं, आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों द्वारा रूस में तोड़फोड़, आतंकवादी हमलों, सामूहिक हत्याओं और साइबर धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों की योजना बनाने और समन्वय के लिए इस्तेमाल किया गया। एफएसबी ने दावा किया कि इन कथित गतिविधियों के कारण महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की जान गई तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। एजेंसी के अनुसार, पावेल डुरोव को अंतरराष्ट्रीय वांटेड सूची में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की जांच जारी है।

दानपेटी लेकर संसद पहुंचे सपा सांसद, केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। राम मंदिर में कथित चढ़ावे और दान चोरी के आरोपों को लेकर बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने संसत भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सपा सांसद हाथों में दानपेटी और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार मंदिर की दानपेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती, वह देश और युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की।

खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों का 32 आतंकवादियों को मारने का दावा

रावलपिंडी। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्खा और बलूचिस्तान के अलग-अलग इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान 32 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया है। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल दुनिया न्यूज़ ने आईएसपीआर के हवाले से बताया कि, 28 व 29 जुलाई की रात खैबर पख्तूनख्खा के खैबर जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर कई लक्षित अभियान चलाए गए। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए फि त्ता अल-ख्वारिज से जुड़े 24 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं, बलूचिस्तान के नुश्की जिले में भी खुफिया आधारित ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में आठ आतंकवादी मारे गए। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के कब्जे से हथियार, गोला-बारूद और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए सुरक्षा बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अज्म-ए-इस्तेक़ाम अभियान के तहत आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पूरी गति से जारी रखेंगी।

लोकसभा में पेश हुआ जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक

► रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, देरी पर सख्त नियम

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल सदन में रखा। इस विधेयक का उद्देश्य देशभर में जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल करना और फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी पर सख्त नियम लागू होंगे। यदि रजिस्ट्रेशन कराने में एक से दो साल की देरी होती है तो जिला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी अनिवार्य होगी। वहीं, दो साल से अधिक की देरी होने पर मामला सीधे अदालत जाएगा और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। इस कानून के तहत अब पूरे देश के

जन्म और मृत्यु के रिकॉर्ड को एक केंद्रीय डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। इससे देश के किसी भी हिस्से में होने वाले जन्म या मृत्यु की जानकारी एक ही जगह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। इस डेटाबेस को मतदाता सूची, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य राष्ट्रीय पहचान पत्रों से भी जोड़ा जाएगा। कोई नागरिक 18 वर्ष का होगा, उसका नाम स्वतः मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। वहीं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकारी रिकॉर्ड से उसका नाम आसानी से हटाया जा सकेगा। इससे सरकारी योजनाओं में होने वाली गड़बड़ाहटों और फर्जी लाभ उठाने की घटनाओं पर रोक लगेगी। नए कानून के लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र सबसे मुख्य दस्तावेज बन जाएगा। अब तक स्कूल में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी नौकरियों में आवेदन के लिए अलग-अलग दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र ही उग्र और पहचान का एकमात्र आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा।

डॉ मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने उस दौर में कई सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी, जब महिलाओं की शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी बेहद सीमित थी। वह लड़कों के कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला बनीं और आगे चलकर भारत की पहली महिला विधायक के रूप में इतिहास रचा। इसके अलावा, उन्हें किसी विधायी परिषद की पहली महिला उपसभापति बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ।

उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए जीवनभर कार्य किया। देवदासी प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह के विरोध और महिला कल्याण से जुड़े कई सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कैंसर रोगियों के उपचार के लिए भी उल्लेखनीय योगदान दिया और चेन्नई में



अद्वार कैंसर संस्थान की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके सामाजिक और मानवीय योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया।

जन्म 1882 - सत्येंद्रनाथ बोस (क्रांतिकारी) - प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। 1886 - मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी - भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थीं। 1887 - अटर्बल्लभा मोहंती - उड़िया साहित्यकार थे। भारत सरकार ने उन्हें साल 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। 1979 - बिष्णुपद मुखर्जी - भारतीय

सदी के जानेमाने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्यशास्त्री थे। 1927 - माधवसिंह सोलंकी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं।

मिथन 1771 - थॉमस ग्रे - 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक। 1969 - अटर्बल्लभा मोहंती - उड़िया साहित्यकार थे। भारत सरकार ने उन्हें साल 1960 में पद्म श्री से सम्मानित किया था। 1979 - बिष्णुपद मुखर्जी - भारतीय

2019 - सुबीर गोकर्ण - भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे।

1923 - गोविन्द चन्द्र पाण्डे - 20वीं

1936 - अमेरिका के हवाई में अंग्रेजी भाषा का पहला अखबार प्रकाशित हुआ।

1980 - वानुआतो देश को स्वतंत्रता मिली।

1836 - देश की पहली महिला विधायक और समाज सुधारक एस. मुथुलक्ष्मी रेड्डी का जन्म।

2000 - संयुक्त राष्ट्र ने इस्रायल द्वारा खाली किफे क्षेत्रों में शांति सेना की तैनाती प्रारम्भ की।

1909 - राइट बन्धुओं ने सेना के लिए पहला विमान बनाया।

2001 - श्रीलंका सरकार ने मुक्ति चीतों पर से प्रतिबंध हटाने से इन्कार किया।

1942 - जर्मन की सेना ने बेलारूस के भिस्क में 25000 यहूदियों की हत्या की।

2002 - कनाडा ने अलकायदा सहित सात संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया।

1957 - एक्सपोर्ट रिस्क इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना।

2006 - हालीवुड अभिनेत्री पामेला एडरसन ने गायक किड रॉक से विवाह किया।

1966 - इंग्लैंड ने फुटबॉल का

करोड़ों रुपये के घोटाले में सल्लिभ आरोपी को आंध्र प्रदेश से किया गिरफ्तार

हरियाणा मेल ब्यूरो

सोहना। शहर थाना पुलिस आंध्रप्रदेश से करोड़ों रुपये के घोटाले में सल्लिभ आरोपी को गिरफ्तार करके लाई है। जिसे अदालत ने पुलिस को चार दिन रिमांड पर मामले से संबंधित पूछताछ के लिए भेजा है। रिमांड पर आया घोटाले में सल्लिभ आरोपी से हरियाणा पुलिस की इन्फोमिक्स शैल ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। शहर थाना से पुलिस की गठित टीम दोस दिन पहले करोड़ों रुपये के घोटाले में सल्लिभ आरोपी लोवा राजू कांदी रैली निवासी राजा सुंदरी आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार करके मंगलवार की रात को वापस सोहना पहुँची है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी को आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री से गिरफ्तार किया था। जिसे अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की मांग पर चार दिन रिमांड पर भेजा है। इससे पहले शहर थाना पुलिस ने इस करोड़ों रुपये के घोटाले में 13 आरोपियों को बीते करीब 7 साल में गिरफ्तार कर जेल भेजवाने का काम किया है। गिरफ्तार आरोपी को अदालत बाद भगौड़ा घोषित किया हुआ था। जानकारी के अनुसार श्री राम फाइनंश एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों ने करीब 400 लोगों को चिटफंड करते हुए करीब 8 करोड़ रुपये लगवाया था। 400 के करीब लोगों को एजेंसी में काम करने वाले साढ़े पांच वर्ष में दोगुणा और साढ़े छह साल में तीन गुणा नकदी वापस लौटाने का लालच देकर फजीबांड़ा किया था। पुलिस ने 2019 में करीब 150 पीडितों की हस्ताक्षर युक्त शिकायत पर एजेंसी में काम करने वाली कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करके लोगों से नकदी ठगने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में पुलिस अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

खबरें फटाफट

77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, सोहना में 30 जुलाई को

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार के पर्यावरण संरक्षण एवं हरित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 77वां जिला स्तरीय वन महोत्सव 30 जुलाई को जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी, सोहना में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कौतिकेय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। जिला वन अधिकारी सुरेंद्र दांगी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, हरियाणा डेयरी विकास निगम के चेयरमैन राम अवारार गर्ग, गुरुग्राम की महापौर राजरानी मल्होत्रा, भाजपा के गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रीत त्यागी एवं गुरुग्राम महानगर जिला अध्यक्ष अजीत यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं वन विभाग की ओर से कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वह कार्यक्रम गुरुवार को 12 बजे अपराह्न से शुरू होगा। वन महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा हरित आवरण बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों एवं नागरिकों से कार्यक्रम में सहभागिता कर अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा पर्यावरण संरक्षण के इस जन अभियान को सफल बनाने का आान किया है।

गांव मुशेदपुर में 30 जुलाई को जिला प्रशासन का रात्रि ठहराव

गुरुग्राम। जिला प्रशासन गुरुग्राम की ओर से गुरुवार, 30 जुलाई को जिला के फर्रुखनगर ब्लॉक के गांव मुशेदपुर में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सीटीएम ज्योति नागपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डीसी उत्तम सिंह रात्रि ठहराव के दौरान भागीणों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सेनी के दिशा निर्देशों की अनुपालना जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी ढंग से की जा रही है। इसी कड़ी में समाधान शिबिर के साथ ही रात्रि ठहराव कार्यक्रम भी निरन्तर किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक व व्यक्तिगत समस्याओं को सुन कर उनका समाधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार की जनहितकारी नीतियों की जानकारी देने के लिए विभागीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे।

जीयू में गुंजी कारगिल की वीरगाथाएं, युवाओं में जगी देशभक्ति

गुरुग्राम। गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम के विद्यार्थी कल्याण विभाग एवं जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र के संयुक्त तत्वावधान में आज मुख्य सभागार में कारगिल विजय दिवस का भव्य एवं गरिमामय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करना तथा युवा पीढ़ी में देशप्रेम की भावना को और प्रबल करना था। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपनी मधुर आवाज में देशभक्ति गीतों से सबका मन मोह लिया क कार्यक्रम की प्रस्तावना छत्र कल्याण विभाग के अधिष्ठाता प्रो. राकेश कुमार योगी ने रखी कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजय कौशिक रहे। मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल संजय सी. मेरन्तन, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम (रिटायर्ड) उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में जम्मू कश्मीर अध्ययन केन्द्र के राष्ट्रीय सचिव रंजन चौहान ने अपने विचार रखे। संरक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. संजय आरोड़ा उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कारगिल युद्ध की वीरगाथाओं, शहीदों के बलिदान और भारतीय सशस्त्र बलों की अदम्य वीरता पर प्रकाश डाला। वहीं दूसरी ओर इस अवसर पर गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलगुरु प्रोफेसर संजय कौशिक ने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए वीर जवानों ने जो अमूल्य बलिदान दिए, वे हमारी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत हैं। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आज का यह आयोजन छात्रों के हृदय में देशप्रेम की भावना को और गहराई से स्थापित करेगा। मुख्य वक्ता रंजन चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार के साथ मिलकर कारगिल विजय दिवस मनाना मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं कामना करता हूँ कि हमारे युवा इन वीरों के आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र सेवा में सदैव आगे रहें। आगे उन्होंने युद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों से छात्रों को अवगत कराया।

सेक्टर-78 और 79 में 2.4 किमी लंबे सर्विस रोड बनाएंगा जीएमडीए

- 4.62 करोड़ होंगे खर्च
- दोनों ओर 1.2-1.2 किमी सर्विस रोड के साथ बनेगा नया स्टॉम वाटर ड्रेन
- यातायात होगा सुगम और जलभराव से मिलेगी राहत

हरियाणा मेल ब्यूरो

गुरुग्राम। न्यू गुरुग्राम में सड़क संपर्क और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) सेक्टर-78 और 79 में 4.62 करोड़ की लागत से 2.4 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड नेटवर्क का निर्माण करेगा। परियोजना के तहत दोनों ओर 1.2-1.2 किलोमीटर लंबे सर्विस रोड बनाए जाएंगे। साथ ही वर्षा जल की त्वरित निकासी सुनिश्चित करने के लिए नया स्टॉम वाटर ड्रेन भी तैयार किया जाएगा, जिसे मास्टर ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी



अधिकारी श्री पी. सी. मीणा ने बताया कि नए सर्विस रोड सेक्टर की आंतरिक सड़कों को मुख्य कैरिजवे से जोड़ेंगे। इससे स्थानीय निवासियों और दैनिक आवागमन करने वाले लोगों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी तथा मुख्य सड़क पर अनावश्यक यातायात का दबाव भी कम होगा।

उन्होंने कहा कि आसपास के सेक्टरों के वाहनों के लिए एलएव सर्विस रोड उपलब्ध होने से मुख्य कैरिजवे पर यातायात अधिक व्यवस्थित रहेगा और पूरे कॉरिडोर में वाहनों की आवाजाही सुरक्षित एवं सुचारु होगी।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् गायन के बाद होगा राष्ट्रीय गान जन-गण-मन

- वंदे मातरम् व जन-गण-मन के दौरान खड़े होना अनिवार्य, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देशः डीसी

- डीसी उत्तम सिंह ने जिला में गृह मंत्रालय के आदेशों की अनुपालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

हरियाणा मेल ब्यूरो

गुरुग्राम। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् तथा राष्ट्रीय गान जन-गण-मन के गायन एवं वादन से संबंधित पूर्व में जारी किए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का एकीकरण करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का भावना को और अधिक सुदृढ़ करना तथा पूरे देश में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आदेशों के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् प्रस्तुत किया जाएगा और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान जन-गण-

मन का गायन या वादन किया जाएगा। इस दौरान सभी को अनिवार्य रूप से खड़ा होना होगा।

डीसी उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए जिला में आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के गायन और वादन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों को एक ही दस्तावेज में समाहित किया गया है, ताकि विभिन्न अवसरों पर इनके प्रस्तुतीकरण को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के अवसर, प्रक्रिया और क्रम का विस्तृत उल्लेख परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 में किया गया है।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय के अवसर, प्रक्रिया और क्रम का गायन या वादन किया जाना हो, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् प्रस्तुत किया जाएगा और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन या वादन किया जाएगा।

भारी बारिश से ज्वार व बाजरे की फसल को हुआ नुकसान



हरियाणा मेल ब्यूरो

सोहना। मंगलवार को हुई भारी बारिश के किसानों द्वारा बिजाई की हुई ज्वार व बाजरे की फसल नुकसान हुआ है। बारिश के साथ तेज हवा ने ज्वार व बाजरे की फसल को गिरा दिया। जिससे पशुओं का चारा खराब होने और किसान को मिलने वाली फसल पैदावार कम होने की आसार बन गए है।

मंगलवार को इस बार की अब तक की सबसे तेज बारिश हुई। इस बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारी बरसात का असार ज्वार व बाजरे की फसल पर भी पड़ा। किसानों द्वारा समय से पहले बिजाई की गई ज्वार की फसल छह से साढ़े छह फुट की उंचाई तक लंबी है। लेकिन बारिश के साथ

बाजरे की फसल को कम तथा ज्वार की फसल की अधिक उंचाई होने से नुकसान हुआ है। किसान अपने खेत में बरसाती पानी जमा न होने दे। जहां पर पानी जमा होता है। वहां फसल की जड़ें कमजोर होती है। इसलिए फसल को सुरक्षित रखने के लिए जलभराव वाले हालातों को समाप्त करें।

–अनिल कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी कृषि विभाग सोहना

चली तेज हवाओं ने एक एकड़ जमीन में 30 से 40 फीसदी फसल गिर गई। जमीन पर गिरि फसल से न तो पशु के चारे के मतबल की है और न ही किसान को उससे अनाज प्राप्त होगा। बरसात के किसानों को हुआ नुकसान से काफी झटका दिया है। जिन किसानों ने ज्वार व बाजरे की फसल बिजाई देर से की। उस फसल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इस बार बरसाती मौसम की शुरूआत में फसलों को हुआ बरसात से उंचाई तक लंबी है। लेकिन बारिश के साथ

लोकल से ग्लोबल की सोच को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं: राजरानी मल्होत्रा

- अंतरराष्ट्रीय एसडीजी कॉन्क्लेव कॉन्फेरेंसिया-2026 का मेयर राजरानी मल्होत्रा ने किया शुभारंभ
- 44 से अधिक विद्यालयों के 600 विद्यार्थियों ने लिया भाग

हरियाणा मेल, एजेंसी

गुरुग्राम। डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर-49 में बुधवार को दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव कॉन्फेरेंसिया-2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की थीम पर आयोजित इस प्रतिष्ठित कॉन्क्लेव में 44 से अधिक विद्यालयों के लगभग 600 विद्यार्थियों एवं प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता, नेतृत्व क्षमता, नीति निर्माण की समझ तथा



जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित करना रहा।

कार्यक्रम में गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी के उपाध्यक्ष अनिल कुमार राव तथा नगर निगम गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने विद्यार्थियों को समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज के युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान के परिवर्तनकारी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से लोकल से ग्लोबल की सोच अपनाने, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और नागरिक उत्तरदायित्व को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आान किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा चलाए जा रहे जनहित एवं स्वच्छता अभियानों में युवाओं की

नया स्टॉम वाटर ड्रेन भी बनेगा

परियोजना के तहत सर्विस रोड के साथ नया स्टॉम वाटर ड्रेन भी बनाया जाएगा। इसे मौजूदा मास्टर ड्रेनेज नेटवर्क से जोड़ने के बाद मानसून के दौरान वर्षा जल की तेज निकासी संभव होगी। इससे सर्विस रोड पर जलभराव नहीं होगा और भारी बारिश के दौरान भी यातायात प्रभावित नहीं होगा। मीणा ने बताया कि 4.62 करोड़ की इस परियोजना को 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे सेक्टर-78 और 79 के नियोजित विकास को गति मिलेगी तथा न्यू गुरुग्राम की सड़क एवं ड्रेनेज अवसंरचना और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि जीएमडीए आधुनिक, सुरक्षित और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा मिल सके और शहर के दीर्घकालिक विकास को गति मिलती रहे।

मानसून प्रबंधन में लापरवाही पर नगर निगम का जेई निलंबित

- पंपिंग मशीनरी उपलब्ध नहीं कराने पर एजेंसी को कारण बताओ नोटिस

हरियाणा मेल, एजेंसी

गुरुग्राम। मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने में लापरवाही पर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर-14 एवं सेक्टर-17सी में समय पर पंपसेट तैनात करने पर बुधवार को कनिष्ठ अभियंता सुमित चहल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी ओर पंपिंग मशीनरी उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित एजेंसी द हजारी लाल को-ऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन सोसायटी लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार 28 जुलाई को हुई भारी



वर्षा के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वर्षा से पूर्व सभी संवेदनशील एवं जलभराव संभावित क्षेत्रों में पंपसेट तैनात रखने तथा त्वरित जलनिकासी सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सेक्टर-14 एवं सेक्टर-17सी में समय पर पंपसेट तैनात नहीं किए गए, जिससे जलभराव लंबे समय तक बना रहा और आम नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के तहत कनिष्ठ अभियंता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसी क्रम में वार्ड-25 में

मानसून सीजन के लिए अनुबंधित पंपिंग मशीनरी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि बार-बार मौखिक एवं टेलीफोनिक निर्देश दिए जाने के बावजूद जलभराव वाले चिन्हित स्थानों पर आवश्यक पंपिंग मशीनरी तैनात नहीं की गई। 28 जुलाई की वर्षा के दौरान भी मशीनरी समय पर उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी रही और स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर निगम ने एजेंसी को दो दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में एजेंसी के विरुद्ध कार्य आदेश समाप्त करने, सुरक्षा राशि जप्त करने, ब्लैकलिस्ट करने तथा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बरसात में सड़कें बर्नीं जाल, हर कदम पर हादसे का सवाल



हरियाणा मेल ब्यूरो

सोहना। मंगलवार को हुई भारी बारिश ने शहर की सड़कों की हालत और अधिक खराब कर दी। जलभराव तथा लगातार वाहनों के आवागमन से कई सड़कों पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। बारिश का पानी भर जाने के कारण वाहन चालकों को इनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे किसी भी समय गंभीर हादसा होने की आशंका बनी हुई है। पिछले करीब एक महीने से रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर की आधा दर्जन से अधिक सड़कों पर गड्ढे बन चुके थे। मंगलवार की तेज बारिश ने इन्हें और गहरा कर

दिया। सड़कों की जर्जर हालत के चलते वाहन चालकों को धीमी गति से और बेहद सावधानी के साथ निकलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्रों का कई सड़कों के नीचे सीवर लाइन बिछी हुई है। ऐसे में जलभराव के दौरान खुले या क्षतिग्रस्त सीवर चैबर दिखाई नहीं देते। इससे विशेष रूप से स्कूटी और बाइक सवारों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा अधिक रहता है।

नगर परिषद सोहना के कार्यकारी अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि गड्ढों वाली सड़कों का सर्वे कराया जाएगा। जहां अधिक गहरे गड्ढे हैं, उन्हें तत्काल भरवाया जाएगा। बरसात का

बालूदा मार्ग की हालत सबसे खराब

शहर के बालूदा मार्ग की स्थिति सबसे अधिक खराब बताई जा रही है। करीब दो किलोमीटर लंबे हिस्से में जगह-जगह गहरे गड्ढे बने हुए हैं। आमने-सामने से आने वाले वाहनों की बचाने में चालकों को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा दुर्गुी नंबर एक से फव्वारा चौक जाने वाली सड़क पर पावर हाउस के सामने गहरे गड्ढे बन गए हैं। सांप की नंगली मोड़ पर सड़क के बीचोबीच गड्ढे हैं। बस स्टैंड मार्ग, फ्रेंड्स कॉलोनी की सड़कें और नागरिक एक्सप्रेसवे मार्ग भी बदहाल हैं। इन मार्गों से प्रतिदिन गुजरने वाले लोगों को दुर्घटना का भय बना रहता है।

मौसम समाप्त होने के बाद सड़कों को नए सिरे से बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा।

द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्टंट करना पड़ा महंगा, कार समेत युवक काबू हरियाणा मेल, एजेंसी

गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार में कार चलाकर खतरनाक स्टंट करने वाले युवक को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्टंट में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की है। आरोपी को पहचान 24 वर्षीय प्रणव मनचंदा के रूप में हुई है। वह गुरुग्राम के सेक्टर-54 स्थित द पाम सिटी का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से कार चलाते हुए स्टंट कर रहा था। इस दौरान बचाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जो तेजी से वायरल हो गया। वीडियो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद उसकी जांच की गई। प्रारंभिक जांच में वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने और सार्वजनिक मार्ग पर अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा को खतरे में डालने की बात सामने आई।

नमो भारत आरआरटीएस बहरोड तक जाएगी: राव इंद्रजीत

- बावल से आगे बहरोड तक की मंजूरी के बाद राजस्थान को भी मिलेगा इसका फायदा

हरियाणा मेल ब्यूरो

गुरुग्राम। हरियाणा के साथ राजस्थान के लोगों के लिए एक बार फिर खुशी कीलहर है की नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को बहरोड तक मंजूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम सांसद व केन्द्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय शहरी विकास एवं हाउसिंग मंत्रालय की ओर से सराय कालेखां से गुरुग्राम -बावल नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को बावल से आगे बहरोड तक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय वित्त विभाग को पत्र लिखकर इसकी मंजूरी देने को कहा है। राव ने कहा कि नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर को



वर्षों पूर्व प्रथम पेज के निर्माण में नीरारणा बहरोड तक मंजूर किया गया था लेकिन इसे बाद में कभी धारूहेड़ा तक और कभी बावल तक सीमित करके छोड़ दिया गया। धारूहेड़ा व बावल तक सीमित करने के कारण अनेक सामाजिक संगठनों व राजस्थान के लोगों की जन आवाज इस योजना को पूर्व की तरह बहरोड तक करने की उठ रही थी। राव इंद्रजीत ने कहा कि बहरोड तक एक्सप्रेसवे की फाइनल फाइनंसे मंजूरी के लिए इस माह जुलाई में भेजी गई है।

भागीदारी शहर के सतत विकास को नई दिशा दे सकती है।

संयुक्त आयुक्त सपना यादव ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यालय द्वारा आयोजित इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों में नेतृत्व, संवाद, नीति निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से नगर निगम के स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जनसागरकता अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आान किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने नेतृत्व क्षमता, ताकिक सोच, संवाद कौशल और टीमवर्क का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या चारू मैनी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि कॉन्फेरेंसिया-2026 जैसे आयोजन विद्यार्थियों को वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने, नेतृत्व कौशल को निखारने तथा जिम्मेदार एवं संवेदनशील नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं।

तहसील पहुंचा वकीलों की हड़ताल का असर

कामकाज छोड़ हड़ताल का हिस्सा बन तहसील में बैठे वकील

सुरेन्द्र इंदौरा, हरियाणा मेल

रेवाड़ी। एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत वकीलों ने तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों से समर्थन मांगा। वकीलों ने भी उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए बिना एक पल की देरी किए अपने समर्थन की घोषणा करते हुए कामकाज ठप्प कर दिया। यह घोषणा होते ही वकीलों ने अपना सामान समेट लिया और हड़ताल का हिस्सा बन गए। वकील तहसील परिसर में डीड राइटिंग का काम करते हैं। इस हड़ताल से जहां राजस्व पर असर पड़ा, वहीं अपने काम को लेकर तहसील में आने वाले लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। उनके काम नहीं हुए, इसलिए उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। तहसील सूत्रों की मानें तो हड़ताल का ज्यादा असर नहीं दिखा, वकीलों के साथ ही यहां अरजी नवीस का काम करने वालों के कारण करीब 25 रजिस्ट्री हुई।

गौतलब है कि कोर्ट में बैठे वकील एसडीएम के तबादले की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत हैं। वकीलों ने काम छोड़ हड़ताल की हुई है। हालांकि पिछले



दिनों प्रशासन अथवा सरकार के आदेश पर एसडीएम को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लेकिन वकील उनके तबादले की मांग पर अड़े हुए हैं।

जानकारी के अनुसार अपने आंदोलन को और मजबूती देने के उद्देश्य से वकील आज तहसील कार्यालय पहुंचे और यहां डीड राइटिंग का काम करने वाले वकीलों का समर्थन मांगा। वकीलों ने भी उनका साथ देते हुए कामकाज छोड़कर हड़ताल कर दी। आज की हड़ताल के कारण रोजाना की तरह ज्यादा रजिस्ट्री नहीं हो पाई, जिससे सरकार

को राजस्व की कुछ हानि का भी समाचार है। हड़ताल के कारण अपने काम के लिए तहसील में आने वाले लोगों को भी काम नहीं होने से परेशानी झेलनी पड़ी। सुंदर लाल नामक एक युवक ने बताया कि उसे एक हल्कनामा टाईप करना था, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। इधर एक तहसील अधिकारी ने बताया कि आज करीब 25 रजिस्ट्री हुई हैं। उन्होंने बताया कि वकीलों को आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, जो उन्होंने नहीं की। तहसील में वकीलों के अलावा अरजी नवीस बैठे हैं, जिन्होंने काम किया है।

धम्म चक्कपवत्तन दिवस पर बुद्ध के संदेश को अपनाने का किया आह्वान

हरियाणा मेल ब्यूरो

रेवाड़ी। बौद्ध धम्म के अनुयायियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा आज स्थानीय बाबा ध्यान दास की बगीची में धम्म चक्कपवत्तन दिवस श्रद्धा, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तथागत बुद्ध के प्रथम उपदेश, धम्म के मूल सिद्धांतों तथा समता, करुणा और मानव कल्याण के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करना था। कार्यक्रम के संयोजक महावीर प्रसाद, दिनेश कुमार बौद्ध एवं नानक चंद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान तथागत बुद्ध एवं भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं के समक्ष ज्ञान रूपी प्रकाश की प्रतीक मोमबत्तियों प्रज्वलित कर तथा पुष्प अर्पित करके किया गया। राजेश बौद्ध



ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध वंदना प्रस्तुत की। महावीर प्रसाद ने निर्माणाधीन आनन्द बुद्ध विहार के उद्देश्य, भावी स्वरूप एवं आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह बुद्ध विहार केवल पूजा-अर्चना का स्थान नहीं होगा, बल्कि धम्म अध्ययन, ध्यान, पुस्तकालय, सामाजिक सेवा, नैतिक शिक्षा तथा युवा मार्गदर्शन का एक समर्पित केंद्र विकसित किया जाएगा, जहां भगवान बुद्ध एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर के मानवीय एवं संवैधानिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार

किया जाएगा। इस अवसर पर सेवास्तंभ के जिला प्रधान भगत सिंह बौद्ध, माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था के प्रधान बुद्ध राम पंचार, मानव कष्ट निवारण समिति के प्रधान स्योकरणा मेहरा, जाटव सभा के हरिकिशन, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी राज कुमार 'जलवा', ईश्वर सिंह सुठाणी, राम निवास नाहरवाल, प्रताप सिंह, नरेंद्र बौद्ध, मुरारी लाल सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।

अवैध खनन पर सख्ती, 238 वाहन जब्त, 60 मामलों में एफआईआर दर्ज

हरियाणा मेल, एजेंसी

नारनौला। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बुधवार को आयोजित बैठक में खनन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अब तक अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त 238 वाहनों को जब्त किया जा चुका है, जबकि 60 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। प्रशासन लगातार अभियान चलाकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में जुटा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आंतरी, बिहारीपुर, जैनपुर, बायल, पंचनोला, गढ़ी, बसीरपुर और घाटासेर गांवों में अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रास्तों को जेसीबी मशीनों की सहायता से खाइयां खोदकर बंद कराया गया है। हाल ही में पंचनोला गांव में अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन भी जब्त की गई है। इसके अलावा बापड़ोली गांव के नदी क्षेत्र में साधारण रेत के अवैध उत्खनन का मामला सामने आने पर संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई है।

एनजीटी ने हरियाणा सरकार को जारी किया नोटिस

हरियाणा मेल, एजेंसी

कैथल। खुराना गांव स्थित लैंडफिल के साइट पर कथित पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन और ठोस कचरा प्रबंधन में अनियमितताओं के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने हरियाणा सरकार और संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2026 को होगी। गांव खुराना के निवासियों की ओर से दायर आवेदन पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। अधिकरण ने कहा कि याचिका में पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया

है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए अधिकरण ने आवेदक को तीन दिन के भीतर याचिका की प्रति उपलब्ध कराने और एक प्रतिवादी पर विधिवत तामील कराने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद खुराना गांव के लोगों में उम्मीद जगी है कि लंबे समय से उठाए जा रहे पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अब ठोस कार्रवाई होगी। ग्रामीणों का कहना है कि लैंडफिल साइट के कारण क्षेत्र में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने इस कानूनी लड़ाई में राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और विधायक आदित्य सुरजेवाला के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया।

रोड़ पर निर्माण कार्य के दौरान साइन बोर्ड लगवाएं सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक में बोले डीसी

सड़क सुरक्षा समिति एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी की समीक्षा बैठक में बोले डीसी

हरियाणा मेल ब्यूरो

रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा कि जिले में किसी भी रोड़ पर निर्माण या परम्मत का कार्य के दौरान संबंधित विभाग या एजेंसी साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। बिना साइन बोर्ड के दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी विभाग या एजेंसी लापरवाही नहीं बरते। डीसी अभिषेक मीणा ने बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

डीसी ने एनएच-8 पर जयसिंहपुरा से धारुहेड़ा तक ग्रिल लगवाने के निर्देश देते हुए कहा कि रोड़ पर सुरक्षा की दृष्टि से ग्रिल लगवाने के साथ-साथ अवैध कट



भी पूरी तरह से बंद किए जाएं। इसके साथ-साथ उन्होंने बनीपुर चौक पर चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाने और रोड़ पर जमा हो रहे पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। डीसी ने नारनौल बाईपास सहित अन्य रोड़ पर लाइट, नालों की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने हाईवे पर अवैध रूप से खड़े ट्रकों

व अन्य वाहनों पर निरंतर कार्रवाई अमल में लाने के भी आदेश दिए। डीसी अभिषेक मीणा ने कहा है कि जिले में सड़कों को वाहन चालकों के लिए सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए समय-समय पर सड़कों पर डिवाइडर, गति अवरोधक, सफेद पट्टी, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट, आवश्यकता अनुसार ग्रिल लगाए जाने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस, लोक निर्माण

विभाग, नगर परिषद, एचएसबीपी, एचएसआरडीसी, मार्केटिंग बोर्ड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आदि विभाग सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के प्रति संवेदनशील रूख अपनाने। डीसी ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत स्कूलों के वाहनों की निरंतर जांच करने के निर्देश देते हुए कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने सड़क नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी जुमाना के साथ-साथ नियमानुसार वाहन जन्म करने की कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, एसडीएम बावल संजीव कुमार, एसडीएम कोसली विजय यादव, सीटीएम जितेंद्र कुमार व डीएसपी संजीव बल्हारा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

सीएम विंडो के नए आदेश के विरोध में संगठनों ने सौंपा ज्ञापन

हरियाणा मेल, एजेंसी

सोनीपत। सोनीपत में मुख्यमंत्री विंडो से संबंधित नए प्रशासनिक आदेश के विरोध में बुधवार को रक्षक सेना भारत और विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी लघु सचिवालय पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उस आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग की, जिसके तहत वर्षों से लंबित शिकायतों को केवल एमिनेंट सदस्य के हस्ताक्षर के आधार पर बंद करने की व्यवस्था की गई है।

संगठनों का कहना है कि शिकायतों का वास्तविक समाधान किए बिना उन्हें बंद करना जनहित के खिलाफ है। इससे आम लोगों का प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह मामला राज्य सरकार और संबंधित मंत्रियों के समक्ष भी



प्रमुखता से उठाया जाएगा। रक्षक सेना भारत के प्रमुख मनजीत तिहाड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री विंडो आम नागरिकों को न्याय दिलाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि एमिनेंट सदस्य की जिम्मेदारी केवल हस्ताक्षर करना नहीं, बल्कि शिकायतों के निष्पक्ष और प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करना है। यदि बिना जमीनी स्तर पर समस्या का समाधान किए शिकायतें बंद की जाती हैं तो इससे जनता का विश्वास प्रभावित होगा और इस व्यवस्था के उद्देश्य पर भी सवाल उठेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि नए आदेश से लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही

कम हो जाएगी। संगठन का आरोप है कि वर्षों से लंबित मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों को संरक्षण मिलने की आशंका है, जिससे मुख्यमंत्री विंडो की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि विवादित आदेश तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री विंडो पर लंबित सभी शिकायतों की जांच के लिए स्वतंत्र समीक्षा समिति गठित की जाए। संगठन ने यह भी मांग रखी कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो।

बिजली कर्मियों ने किया तीन दिवसीय हड़ताल का ऐलान



हरियाणा मेल, एजेंसी

सोनीपत। सोनीपत में हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं अभियंता संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने निजीकरण की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारी शहर के विभिन्न स्थानों से पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे, जहां सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर न्यायर, बाहर और तेरह अगस्त को प्रदेशव्यापी तीन दिवसीय

हड़ताल का नोटिस दिया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर समय रहते सरकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना था कि बिजली बोर्ड के निगमों के पुनर्गठन के समय सुधार और लाभ का दावा किया गया था, लेकिन विभाग का घाटा कम होने के बजाय लगातार बढ़ा है। कर्मचारियों ने हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की प्रस्तावित योजना, गुरुग्राम और नूंह में निजी बिजली वितरण लाइसेंस तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि एग्री डिस्कॉम गठन की अधिसूचना जारी की गई तो यही ज्ञापन अनिश्चितकालीन हड़ताल का अग्रिम नोटिस माना जाएगा।

राशन गबन के आरोप में डिपो होल्डर पर एफआईआर के आदेश



जबकि पांच शिकायतों को जांच एवं रिपोर्ट के लिए अगली बैठक तक लंबित रखा गया। मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान गांव हरिपुरा के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन डिपो संचालक ने 80 से 90 परिवारों का कई महीनों का राशन हड़प लिया। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित डिपो होल्डर के

खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और शिकायत का निपटारा कर दिया। वहीं सेक्टर-19 पार्ट-1 के निवासियों ने आरोप लगाया कि एचएसबीपी ने पार्क और ग्रीन बेल्ट विकसित करने का वादा करने के बावजूद पिछले 30 वर्षों से इस दिशा में कोई काम नहीं किया। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि प्लॉट आवंटन के समय पार्क के नाम पर उनसे अतिरिक्त राशि भी ली गई थी।

जॉर्जिया में होने वाली अंतरराष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप के लिए नितेश रवाना

हरियाणा मेल, एजेंसी

सोनीपत। प्रताप सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खरखोड़ा के वुशु खिलाड़ी गांव माहरा निवासी नितेश 90 किलोग्राम वर्ग में 31 जुलाई से 4 अगस्त तक जॉर्जिया में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप के लिए बुधवार को रवाना हुआ। इस प्रतिযোগिता के लिए ट्रायल देहरादून में आयोजित किए गए, जिसमें नितेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल कर भारतीय टीम में जगह बनाई। नितेश के चयन पर विद्यालय में खुशी नितेश को कोच विद्यालय प्रधानाचार्या दया दहिया, एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. सुबोध दहिया, वुशु कोच विनोद गुलिया तथा साईं खेलो इंडिया के कोच दिवस कटारिया ने नितेश को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभाशीष दिए। इस अवसर पर एकेडमिक डायरेक्टर डॉ. सुबोध दहिया ने कहा कि नितेश पहले



भी राष्ट्रीय स्तर पर छह पदक जीत चुके हैं और उन्हें विश्वास है कि वह जॉर्जिया में भी भारत के लिए पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। नितेश ने वुशु कोच विनोद गुलिया, एसएआई खेलो इंडिया सेंटर के कोच दिवस कटारिया तथा अपने माता-पिता को दिया। उत्कृष्ट प्रशिक्षण, अनुशासन और निरंतर प्रोत्साहन की बदौलत ही वह भारतीय टीम में चयनित हो सके हैं।

हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन

उदय चंद माथुर, हरियाणा मेल

हथौन। नूंह व गुरुग्राम में वितरण के लिए समानांतर लाइसेंस को रद्द करने,एग्री डिस्कॉम,स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में बुधवार को पलवल स्कूल के समक्ष हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन की अध्यक्षता ऑल हरियाणा पॉवर कारपोरेशन वर्कर यूनियन स्कूल सचिव राजेश शर्मा , हरियाणा बिजली बोर्ड वर्कर यूनियन स्कूल सचिव और हरियाणा पॉवर इंजीनियर एसोसिएशन कुलदीप यादव एक्सएन ने संयुक्त रूप से की संचालन समू न खान के द्वारा किया गया ।प्रदर्शन के बाद अधीक्षक अभियंता कार्यालय से उपायुक्त पलवल के कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम जापान अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्री उत्सव आनंद के मार्फत दिया गया ।कर्मचारियों को संबोधित करते हुए आल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य उपप्रधान

जितेन्द्र तेवतिया ,कार्यकारी अभियंता कुलदीप यादव ,यकेश बनचारी ने कहा कि हरियाणा सरकार बिजली में समानांतर वितरण लाइसेंस स्मार्ट मीटर एग्री डिस्कॉम के फैसलों को तत्काल निरस्त करने की मांग करता है ज़ापान में आयोग द्वारा गठित तथाकथित विशेषज्ञ समिति को भी तत्काल भंग करने की मांग की गई। जापान में कहा गया कि यह समिति मनमाने एवं असंवैधानिक तरीके से गठित की गई है तथा इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक मामले में निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यक विश्वसनीयता और निष्पक्षता से वंचित है। उल्लेखनीय है कि इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने नूंह व गुरुग्राम में बिजली वितरण का लाइसेंस देने की याचिका हरियाणा पावर रेगुलेटरी कमीशन दायर की है। जिसका बिजली कर्मचारियों व इंजीनियर्स के अलावा संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर रघुबीर सिंह ने भी किसानों तरफ से अपना आंदोलन में समर्थन किया गया ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के



उप प्रधान जितेन्द्र तेवतिया ने कहा कि निजी कंपनियों को समानांतर वितरण लाइसेंस दिए जाने से सार्वजनिक विद्युत वितरण व्यवस्था कमजोर होगी, आम उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का बोझ बढ़ेगा, क्रॉस-सब्सिडी व्यवस्था समाप्त होगी तथा अंततः बिजली क्षेत्र ने कहा कि यदि निजी कंपनियों को सार्वजनिक वितरण नेटवर्क का उपयोग करते हुए केवल लाभकारी उपभोक्ताओं को चुनने की अनुमति दी गई तो इससे राज्य के सार्वजनिक वितरण निगम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं

पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिजली एक अनिवार्य सार्वजनिक सेवा है, इसे निजी लाभ कमाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने दोहराया कि विद्युत अधिनियम किसी भी उपभोक्ता के साथ भेदभाव की अनुमति नहीं देता तथा सार्वजनिक वितरण नेटवर्क पर एकाधिक वितरण लाइसेंसधारियों की व्यवस्था सार्वभौमिक एवं समान विद्युत आपूर्ति के सिद्धांतों के विपरीत है।इसके अलावा बिजली कर्मचारियों की पंद्रह सूत्रीय मांग पत्र में शामिल मुख्य माँग जिसमे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, मेडिकल सुविधा लागू करने, पुरानी पेंशन लागू करने,

रिस्क अलाउंस देने की माँगो का समाधान किया जाए, रेली में पावर इंजीनियरों, बिजली कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और चेतवानी दी कि यदि जनहित की इन माँगों की अनदेखी की गई तो आंदोलन की अगली कड़ी में 3अगस्त से 5 अगस्त तक सभी डिवीज़नो पर विरोध प्रदर्शन और 6 से 8 अगस्त तक सभी उपमण्डलों के कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए गांव गांव जाकर सरकार की निजीकरण की नीतियों के बारे में चर्चा करतेहुए समर्थन जुटया जाएगा और 11 अगस्त से 13 अगस्त तक तीन दिवसीय हड़ताल होगी जिसमे सभी कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे ।इसके बाद भी सरकार समाधान नहीं करती है तो और व्यापक एवं तीव्र आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में बिजली कर्मियों के नेता राजन वर्मा, राजकुमार डारग सरजीत सिंह, नरेंद्र सोरोत, वेदपाल तेवतिया, योगराज दीक्षित, वीरपाल, योगेश पाठक, पवन कुमार, चंदर शेखर, नंद किशोर, महेंद्र, इजहार, मनोहरी मौजूद थे।

पार्षद दीपक यादव के खिलाफ लामबंद हुए निगम अधिकारी

हरियाणा मेल, एजेंसी

फरीदाबाद। वार्ड-42 के पार्षद दीपक यादव द्वारा बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय में ताला लगाने और कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा को गाड़ी से उतारकर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बुधवार को पार्षद के खिलाफ निगम अधिकारी और कर्मचारी विरोध में आ गए। एसडीओ, जेई और अन्य कर्मचारियों ने पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया व पार्षद से माफी मांगने की मांग भी की। इससे पहले भी पार्षद व अधिकारी आमने सामने आ चुके हैं। एक मामले में तो अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में पार्षद को जेल भी जाना पड़ा था। मंगलवार को पार्षद दीपक यादव ने बल्लभगढ़ नगर निगम कार्यालय में ताला लगा दिया। दीपक यादव ने कार्यकारी अभियंता डालचंद शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने



विधायक के कहने पर वार्ड में सीवर लाइन का काम रोका हुआ है। जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही पार्षद ने कार्यकारी अभियंता से अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर लेगे। लेकिन पार्षद ने जबूर अधिकारी अभियंता ने कहा कि वह अभी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। वापस आते ही वार्ड में निरीक्षण कर लेंगे। लेकिन पार्षद ने जबूर कार्यकारी अभियंता की गाड़ी की चाबी निकाल ली। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जब तक दीपक यादव माफी नहीं मांगेंगे, धरना प्रदर्शन

जारी रहेगा। हालांकि इंटरनेट मीडिया पर लोग पार्षद के पक्ष में खड़े हुए नज़र आए। लोगों ने कहा कि निगम अधिकारी और कर्मचारी छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को चक्कर कटवाते हैं, उनको परेशान करते हैं। ऐसे में पार्षद ने बल्लभगढ़ कार्यालय पर ताला लगाकर सही किया। पूरे मामले में पार्षद दीपक यादव को अपने साथी पार्षदों का ही साथ मिलता नज़र नहीं आ रहा है। पार्षद अजय बैसला ने कहा कि इस मामले में मेयर को हस्तक्षेप करना चाहिए था। लेकिन मेयर को पार्षदों और जनता को परेशानियों से कोई मतलब नहीं है।

खबरें फटाफट

मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी चोरी

फरीदाबाद। सेहतपुर स्थित सूर्या कॉलोनी में कच्छा गैंग ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और कमरों में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर करीब पांच लाख रुपए के सोने के जेवर, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश चोरी कर फरार हो गए। वारदात के समय परिवार पड़ोस में आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी में गया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता शहनाज ने बताया कि वह पल्ला थाना क्षेत्र के सेहतपुर स्थित सूर्या कॉलोनी में अपनी दो बेटियों के साथ रहती हैं, जबकि उनके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं। उनका मायका भी पड़ोस में ही है। मंगलवार रात को वह दोनों बेटियों के साथ मायके में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गई थीं। रात अधिक होने के कारण सभी वहीं रुक गए। शहनाज ने बताया कि बुधवार सुबह, जब वह अपने घर लौटी तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों में रखा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। चोर अलमारी में रखे कीमती सामान को लेकर फरार हो चुके थे। पीड़िता ने बताया कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए धीरे-धीरे करके सोने के जेवर बनवाए थे। चोर करीब पांच लाख रुपये कीमत के सोने के जेवर, एक लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ नगदी चोरी कर ले गए। उन्होंने कहा कि जल्द ही बेटियों की शादी की तैयारी चल रही थी, इसलिए वर्षों की मेहनत से जेवर बनवाए थे। कॉलोनी निवासी दीपक ने बताया कि घटना के बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दो युवक केवल कच्छा पहने हुए हाथ में लैपटॉप और अन्य सामान लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आशंका है कि वारदात देर रात करीब दो बजे के बाद अंजाम दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी सत्य प्रकाश के मुताबिक पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। संदिग्धों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ गायन के बाद होगा राष्ट्रीय गान ‘जन-गण-मन’

हथौन। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ तथा राष्ट्रीय गान ‘जन-गण-मन’ के गायन एवं वादन से संबंधित पूर्व में जारी किए गए सभी आदेशों एवं निर्देशों का एकीकरण करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना तथा पूरे देश में एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आदेशों के तहत सबसे पहले राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुत किया जाएगा और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का गायन या वादन किया जाएगा। इस दौरान सभी को अनिवार्य रूप से खड़ा होना होगा। उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जानकारी देते हुए जिला में आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के गायन और वादन से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों को एक ही दस्तावेज में समाहित किया गया है, ताकि विभिन्न अवसरों पर इनके प्रस्तुतीकरण को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रगान के अवसर, प्रक्रिया और क्रम का विस्तृत उल्लेख परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2 में किया गया है।

राष्ट्रीय गीत के बाद ही होगा राष्ट्रगान

उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बताया कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सरकारी, शैक्षणिक, सांस्कृतिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों का गायन या वादन किया जाना हो, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ प्रस्तुत किया जाएगा और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का गायन या वादन किया जाएगा। इस क्रम का पालन सभी आयोजनों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

जिला नगर योजनाकार विभाग की अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई: डीटीपी

लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही चार अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा

हरियाणा मेल ब्यूरो

हथौन। जिला नगर योजनाकार विभाग पलवल द्वारा जिले में अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बुधवार को जिला नगर योजनाकार विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से पलवल क्षेत्र में विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों पर व्यापक तोड़फोड़ अभियान चलाया।

कार्रवाई के दौरान लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही चार अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। विभागीय टीम ने चार निर्माणधीन दुकानों, लगभग 80 डीपीसी, 10 से 15 बाइंडी वॉल, कॉलोनी में बनाए गए सड़क नेटवर्क तथा लगाए गए बिजली के



खंभों को जेसीबी मशीनों की सहायता से हटाया। यह कार्रवाई हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम-1975 के प्रावधानों के तहत की गई। तोड़फोड़ अभियान के दौरान इयूटी मजिस्ट्रेट, जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी, फील्ड स्टाफ तथा पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार पलवल अनिल मलिक ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध

कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार सख्ती से अभियान जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियां विकसित करने तथा उनमें निर्माण करने वालों के मसूवों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अवैध निर्माणों को प्रारंभिक अवस्था में ही रोकना है, ताकि भविष्य में आमजन को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न उठानी पड़े। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों में पहले ही चेतवानी बोर्ड लगाए जा चुके हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी विकसित करता है अथवा उसमें निर्माण करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों की हड़ताल, कई मामलों की सुनवाई टली

हरियाणा मेल, एजेंसी

फरीदाबाद। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम योजना के विरोध में बुधवार को वकीलों ने कोर्ट का कामकाज बंद रखा। जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर वकीलों ने कोर्ट के काम का बहिष्कार किया, जिससे कई मामलों की सुनवाई प्रभावित हुई। एलएडीसीएस योजना के तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए जिला स्तर पर वेतन पर वकील नियुक्त करती है। ये वकील ऐसे लोगों के मुकदमे लड़ते हैं, जो निजी वकील करने में सक्षम नहीं होते। जो अपराधी वकील नहीं कर पाएंगे, उनको इस योजना के तहत वकील मुहैया कराया जाएगा। जबकि पहले हीनरन वाले निजी वकीलों को धातुर किया जाता था। वकील जोगिंदर नरवत का कहना



है कि इस योजना से निजी वकीलों का काम कम हो जाएगा। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा असर नए और युवा वकीलों पर पड़ेगा, क्योंकि कानूनी सहायता वाले मामले उन्हें मिलने की बजाय सरकारी नियुक्त वकीलों के पास चले जाएंगे। इसी मांग को लेकर फरीदाबाद सहित हरियाणा के कई जिलों में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों ने सरकार से इस योजना पर दोबारा विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की है। हड़ताल के कारण अदालतों में कई मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी।

बिना अनुमति नहीं लगेंगे कांवड़ शिविर

हरियाणा मेल ब्यूरो

हथौन। जिला में पवित्र सावन मास में कांवड़ यात्रा-2026 के दौरान जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 30 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 (रात्रि जलाभिषेक) तक जिले में संबंधित उपमंडल अधिकारी (नागरिक) एवं पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन कांवड़ शिविर स्थापित नहीं कर सकेंगा।

जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पलवल जिले से गुजरने की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, अव्यवस्था अथवा

कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो। जिलाधीश की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कांवड़ शिविर लगाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक (पलवल, होडल एवं हथौन) से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। शिविर केवल दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर (मथुरा दिशा की ओर) मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। साथ ही दो कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी रखना भी आवश्यक है।

जिलाधीश ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश 30 जुलाई 2026 से 11 अगस्त 2026 की रात्रि जलाभिषेक तक प्रभाव्य रहेंगे। आपात परिस्थितियों एवं संभाव्य की कमी को देखते हुए यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से जारी किए गए हैं।

आदेशों का मुनादी के माध्यम तथा नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों से कराया जाएगा। जिला सूचना

विज्ञान अधिकारी को आदेश जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पलवल को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-223 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधीश डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात, सुरक्षा, स्वच्छता एवं श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि यात्रा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

पुलिस ने साइबर अपराधों से बचाव को लेकर जनहित में जारी की एडवाइजरी

हरियाणा मेल, एजेंसी

फरीदाबाद। हथौन। आमजन को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने और उनकी मेहनत की कमाई की रक्षा करने के लिए पुलिस अधीक्षक पलवल नीतीश अग्रवाल के कुशल निर्देशन में पलवल पुलिस ने एक विशेष साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की है कि वे डिजिटल युग में सजग रहें और अनजान लिंक या झांसे में आने से बचें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में साइबर अपराधी आम लोगों को अलग-अलग तरीकों से अपना शिकार बना रहे हैं।

नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी की गई मुख्य हिदायतें

1. किसी भी स्थिति में अपना बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी या कोई भी व्यक्तिगत जानकारी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।

2. सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर किसी

भी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक करने से बचें।

3. किसी भी अनजान ऐप को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल न करें, खासकर वे ऐप जो रिमोट एक्सेस मांगते हों।

4. पुलिस, कस्टम या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का नाम लेकर यदि कोई व्यक्ति वीडियो कॉल करके डराने या पैसों की मांग करने की कोशिश करे, तो तुरंत समझें कि यह फ्रॉड है और घबरानें नहीं।

5. कोई भी अनजान व्यक्ति यदि खुद को बैंक अधिकारी या किसी कंपनी का प्रतिनिधि बताए, तो उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति के साथ साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो वे तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन/ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पलवल में शिकायत दर्ज कराएं।



संपादकीय

मोबाइल में कैद समाज, मनुष्य से दूर होती मनुष्यता

सभ्यता की पहचान उसके भवनों की ऊंचाई से नहीं, उसके हृदय की गहराई से होती है। कोई समाज कितना विकसित है, इसका सबसे विश्वसनीय प्रमाण उसकी सड़कें, मशीनें या तकनीक नहीं होती; उसका परिचय यह होता है कि किसी अजनबी की पीड़ा देखकर उसके लोग कितनी शीघ्र सहायता के लिए बढ़ते हैं। दुर्भाग्य से हमारा समय इसी कसौटी पर एक कठिन प्रश्न के सामने खड़ा है।

आज यदि सड़क पर दुर्घटना हो जाए, किसी युवक पर रोडवेज में हमला हो, किसी छात्रा की कंटेंट से मृत्यु हो जाए या कोई जीवन-मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, तो सबसे पहले जेब से मोबाइल निकलता है। कैमरा चालू होता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है, लाइव प्रसारण शुरू हो जाता है, लेकिन घायल तक पहुंचने वाले हाथ बहुत कम दिखाई देते हैं। यह दृश्य किसी एक शहर का नहीं, पूरे समाज की बदलती मानसिकता का दर्पण है।

तकनीक ने मनुष्य को अभूतपूर्व शक्ति दी है। उसने दूरी मिटाई, संवाद सरल बनाया और सूचना को व्यापक पहुंच दी। पर हर शक्ति उत्तरदायित्व भी लेकर आती है। जब तकनीक संवेदन पर हावी होने लगे, कैमरा करुणा का स्थान ले ले और लाइक्स तथा व्यूज मनुष्य के जीवन से अधिक मूल्यवान लगें, तब समझ लेना चाहिए कि समस्या मशीन में नहीं, मनुष्य के भीतर जन्म ले चुकी है।

भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र रहा है—परहित सरिस धरम नहीं भाई। हमारे यहां घायल की सेवा पुण्य मानी गई, प्यारे को पानी पिलाना धर्म समझा गया और संकट में पड़े व्यक्ति की रक्षा को मानवता का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया। यही वह भूमि है जहां दधीचि ने अस्थियां दान कीं, कर्ण ने कवच—कुंडल त्याग दिए और असंख्य लोगों ने अपरिचितों के लिए प्राण तक दिए। प्रश्न यह है कि क्या वही समाज आज किसी घायल के सामने खड़े होकर केवल वीडियो बनाने तक सिमटता जा रहा है?

विडंबना यह है कि हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से कहीं अधिक अकेले भी हो गए हैं। संपर्क सुची में हजारों नाम हैं, पर संकट की घड़ी में सहारा देने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं। हम सैकड़ों संदेश पढ़ते हैं, किंतु किसी अनजान की कराह हमारे भीतर वैसी बेचैनी पैदा नहीं करती जैसी कभी किया करती थी। सूचना बढ़ी है, लेकिन संवेदना सिकुड़ती चली गई है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि समाज तमाशबीनों का समाज बनता जा रहा है। जहां नागरिक दर्शक बन जाएं और पीड़ा केवल दृश्य बनकर रह जाए, वहां लोकतंत्र भी कमजोर पड़ने लगता है। लोकतंत्र केवल संविधान से नहीं चलता; वह नागरिकों की करुणा, सहभागिता और उत्तरदायित्व से जीवित रहता है। यदि मनुष्य मनुष्य के काम न आए, तो कानून और व्यवस्था भी सीमित हो जाते हैं।

यह कहना उचित नहीं होगा कि दोष केवल नई पीढ़ी का है। यह समाज की सामूहिक विफलता है। परिवारों में बच्चों को प्रतियोगिता तो सिखाई जा रही है, करुणा नहीं; विद्यालयों में तकनीकी दक्षता पर बल है, किंतु नागरिक संवेदनशीलता पर कम चर्चा होती है; समाज सफलता का उत्सव मनाता है, पर सेवा का सम्मान उतनी ऊंचाई से नहीं करता। परिणाम यह है कि मनुष्य बाहर से चमकदार और भीतर से रिक्त होता जा रहा है।

समाधान तकनीक का विरोध नहीं, उसके विवेकपूर्ण उपयोग में है। मोबाइल कैमरा अपराध का साक्ष्य बन सकता है, न्याय में सहायक और अपराधी को दंड दिलाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन यह तभी सार्थक है जब पहली प्राथमिकता घायल की जान बचाने की हो। वीडियो बाद में भी बन सकता है, पर जीवन चला गया तो वह कभी वापस नहीं आता।

हमें अपने बच्चों को फिर सिखाना होगा कि किसी घायल को अस्पताल पहुंचाना किसी वायरल वीडियो से कहीं बड़ा काम है। यह भी याद दिलाना होगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसके मोबाइल का मॉडल नहीं, उसके हृदय की संवेदनशीलता है। जिस दिन संकट में पड़ा अनजान व्यक्ति भी हमें अपना लगेगा, उसी दिन यह समाज सच आधुनिक कहलाएगा।

प्रगति का अर्थ केवल तेज इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल क्रांति नहीं है। वास्तविक प्रगति तब होगी, जब तकनीक हमारे हाथों में रहे और मनुष्यता हमारे हृदय में। जिस समाज में कैमरे तो जीवित हों, पर करुणा मर जाए, वहां विकास की चमक भी अंततः अंधकार ही सिद्ध होती है।

—ऋषि नारायण आचार्य

विचार-प्रवाह

शिक्षा मंत्री का इस्तीफा किसी की हार नहीं बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अवसर



● डा. नर्मदेश्वर प्रसाद

भारतीय लोकतंत्र में छात्र आंदोलनों का स्वर केवल विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था से जवाबदेही की मांग भी होता है। हाल ही में परीक्षा निष्पक्षता को लेकर उठा आंदोलन इसी व्यापक असंतोष का प्रतीक बनकर सामने आया, जिसमें छात्रों ने अपनी मेहनत और भविष्य की सुरक्षा की मांग की। यह मुद्दा राजनीतिक बहस में घिरता जरूर दिखा, लेकिन इसका मूल सवाल शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा है। किसी मंत्री का इस्तीफा इस समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता, जब तक संस्थागत सुधार न हों। असली चुनौती यह है कि विद्यार्थियों का भरोसा फिर से कायम किया जाए और परीक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष बनाया जाए।

विश्वास रखते हुए उससे जवाब भी माँगता है लेकिन यहीं से राजनीति अपना रंग दिखाने लगती है।

छात्रों की माँग थी कि परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएँ दोबारा न हों। धीरे-धीरे यह आंदोलन राजनीतिक दलों की उपस्थिति से घिरने लगा। सत्ता पक्ष इसे सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि की किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

भारत में डॉक्टर बनने का सपना केवल छात्र का सपना नहीं होता। उसके साथ एक किसान का खेत जुड़ा होता है, एक मजदूर की अथूरी इच्छाएँ जुड़ी होती हैं, एक माँ के गहने गिरवी रखे होते हैं और एक पिता की पूरी सेवा-निवृत्ति की जमा पूँजी दाँव पर लगी होती है। ऐसी स्थिति में यदि परीक्षा की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल प्रश्नपत्र नहीं, करोड़ों परिवारों का विश्वास भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल की देन नहीं था; इसकी जड़ें उन विद्यार्थियों की पीड़ा में थीं जो अपनी मेहनत का न्याय चाहते थे।

इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया कि आज का भारतीय विद्यार्थी पहले की तरह मौन नहीं है। वह प्रश्न पूछता है। वह सूचना का अधिकार भी जानता है और संवैधानिक अधिकार भी। वह अदालत का दरवाजा भी खटखटाता है और लोकतांत्रिक विरोध भी करता है। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब नागरिक व्यवस्था पर ऐसे नारे केवल प्रधानमंत्री का अपमान

नहीं करते बल्कि उस आंदोलन की गरिमा भी कम कर देते हैं जिसके केंद्र में लाखों छात्रों का भविष्य हो। इससे सरकार को यह कहने का अवसर भी मिलता है कि आंदोलन अपनी मूल दिशा से भटक गया है। किसी भी जनांदोलन में जब तर्क की जगह अपशब्द और संवाद की जगह उतेजना ले लेती है, तब सबसे अधिक नुकसान उसी आंदोलन को सीमित प्रशासनिक त्रुटि सिद्ध करने में लगा रहा, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की व्यापक विफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। लोकतंत्र में दोनों का अधिकार है लेकिन प्रश्न यह है कि इस पूरी बहस में छात्र कहाँ रह गया? आज भारतीय राजनीति का बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लगभग हर राष्ट्रीय मुद्दा अंततः नरेंद्र मोदी के समर्थन या विरोध में बदल जाता है। शिक्षा का प्रश्न भी उसी धुवीकरण का शिकार होता दिखाई दिया। अनेक विपक्षी नेताओं ने छात्रों को पीड़ा को मुखरता से उठाया, जो उनका लोकतांत्रिक दृष्टि से देखना चाहिए। NEET को लेकर उठा छात्र आंदोलन और उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ऐसा ही प्रश्न है। यदि किसी मंत्री का इस्तीफा होता है तो उसे न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत पराजय माना जाना चाहिए और न राहुल गांधी अथवा विपक्ष की विजय। यदि उस घटना से शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक विश्वसनीय बनती है, तभी उसका वास्तविक अर्थ होगा।

गालियां, जेन-जी और सहमे हुए अभिभावक



● गजेंद्र सिंह

कॉलेज जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान जंतर-मंतर से जो दृश्य सामने आए, उन्होंने केवल राजनीति को नहीं, समाज को भी आईना दिखाया। सबसे बड़ा झटका शायद उन माताओं-पिताओं को लगा जिन्होंने पहली बार अपने बच्चों के देश भाषा-ज्ञान का सार्वजनिक प्रदर्शन देखा जिसका शब्दकोश उन्होंने कभी खरीदा ही नहीं था।

एमसी-बीसी तो अब पुरानी बात हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो ने, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी को बेहद अश्लील और कल्याणतीत गालियां पूरे आत्मविश्वास और धज के साथ दी जा रही हैं, वहीं **#\$€£&#** जैसी एक्सट्रीम

गालियों ने अनेक अभिभावकों को पहली बार यह एहसास कराया कि नई पीढ़ी की शब्दवली उनसे कई पीढ़ियाँ आगे निकल चुकी है। सवाल उठना स्वाभाविक है क्या यह भाषा स्कूलों में सिखाई जाती है, या फिर यह हमारी नई डिजिटल संस्कृति, सोशल मीडिया और आभासी संसार की उपज है? कुछ शहरों को हमेशा गर्व रहा कि उनकी गालियों की बराबरी कोई नहीं कर सकता लेकिन इन दिनों राजधानी से जो शब्द-संस्कृति प्रसारित हुई, उसने महसूस करा दिया कि दिल्ली के आगे हम सचमुच गांव के सीधे-साधे लोग ही हैं।

सबसे ज्यादा बेचैनी उन परिवारों में है जिनके बच्चे बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं। कई अभिभावकों ने तो सोशल मीडिया रील्स देखना ही कम कर दिया है। कहीं अचानक स्क्रीन पर "पापा की परी" या "मम्मी का राजदुलारा" हाथ में तख्ती लिए ऐसे शब्द बोलता दिखाई न दे जाए जिन्हें घर में कभी सुना तक नहीं गया। डर लाजमी है। आज जो लोग प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक मंचों पर गालियां दे रहे हैं, क्या कल वही पैदा करने के "अपराध" में अपने माता-पिता को भी नहीं लताड़ेंगे? लड़के-लड़कियों के हाथों में पकड़े कार्टोर्ड पर लिखी भाषा ने मम्मियों और पापाओं को

यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कल कहीं यही शब्द उनके हिस्से भी न आ जाएं। डर अब कल्पना नहीं, संभावना बन चुका है। डर के आगे जीत है... जीतो! "कादो बाप रो नाम!"

लेकिन यह सब आज का नहीं है। यह बरसों से जमा होता आ रहा आक्रोश है, विसंगतियों से उपजी कुंठा है, जिसे किसी न किसी रूप में बाहर आना ही था। इसलिए इसे केवल राजनीतिक घटना मानकर टाल किने पर्याप्त नहीं होगा। असल डर इस बात का नहीं है कि गालियां किसे दी जा रही हैं। असली चिंता यह है कि यह भाषा आई कहाँ से? आज जो नेता को खुलेआम अपशब्द कह सकता है, क्या कल उसी सहजता से अपने माता-पिता, शिक्षक, पड़ोसी या समाज से भी उसी भाषा में बात नहीं करेगा? यह मान लेना आसान होगा कि यह सब अचानक हुआ है। सच यह है कि यह वर्षों से जमा होते आ रहे आक्रोश, सामाजिक असंतोष, डिजिटल संस्कृति, तात्कालिक प्रसिद्धि की भूख और संवाद के गिरे स्तर का मिश्रण है। आंदोलन तो केवल उसका मंच बन गया।

सवाल किसी एक दल या एक नेता का नहीं, उस सामाजिक मानस का है जो अहमहमिती व्यक्त करने के लिए अब भाषा

की सारी मर्यादाएँ तोड़ने लगा है। यही कारण है कि घर-घर में चर्चा केवल आंदोलन की नहीं, जेन-जी की हो रही है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन यदि अगली पीढ़ी संवाद की जगह गाली को अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावी माध्यम मानने लगे तो चिंता केवल सत्ता की नहीं, पूरे समाज की होनी चाहिए।

घर-घर में एक ही चर्चा है क्या सचमुच यही जेन-जी है? विडंबना यह भी है कि जो लोग स्वयं रोजगार की बातचीत में गालियों का भरपूर प्रयोग करते हैं, वे भी इस नई शब्दवली से हैरान हैं। उन्हें लग रहा है कि गालियों का भी अब नया संस्करण आ गया है, जिसकी प्रस्तुति, आत्मविश्वास और सार्वजनिकता सब कुछ अलग है। भेजा तो बच्चों को पढ़ने था, लेकिन वे भाषा का कौन-सा पाठ पढ़कर लौटे? अब हाल यह है कि कई अभिभावक सुबह-सुबह बच्चों को संस्कार, सुभाषित और प्रेरक रील्स भेज रहे हैं। मानो वर्षों की उपेक्षा की भरपाई कुछ ब्लाटसॉप सेंडिंग्स से हो जाएगी। लेकिन सच यह है कि कुएं में भांग पड़ने के बाद खुमारी तो चढ़ेगी ही। इस पूरे प्रसंग का सबसे गंभीर प्रश्न राजनीतिक नहीं, सामाजिक है। कल सरकार बदल जाएगी।

सत्ता किसी और के हाथ में होगी। आंदोलन समाप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चे हमारे ही रहेंगे, परिवार हमारे ही रहेंगे और समाज भी हमारा ही रहेगा।

जब व्यवहार बिगड़ेगा तो उंगली अंततः माता-पिता पर ही उठेगी "संस्कार क्यों नहीं दिए?" मगर संस्कार भाषणों से नहीं, घर के वातावरण, संवाद और अनुकरण से बनते हैं। यदि समाज स्वयं अहमहमिती की भाषा को गाली में बदल देगा, तो अगली पीढ़ी उसे ही सामान्य मानेगी। मनीषिज्ञान भी कहता है कि आक्रामक भाषा अक्सर भीतर की कुंठा, असुरक्षा और असंतोष की अभिव्यक्ति होती है। यदि ऐसा है, तो यह केवल राजनीति का संकट नहीं, समाज का भी संकट है। सुना है आंदोलन में शामिल युवाओं की पहचान और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो उसके सामाजिक और पारिवारिक परिणाम भी सामने आएंगे। राजनीतिक दल अपने-अपने लाभ-हानि का हिसाब लगा लेंगे, लेकिन परिवारों के सामने खड़े प्रश्न चुनावी नतीजों से हल नहीं होंगे। आखिरकार, हर समाज को यह तय करना पड़ता है कि वह अपनी अगली पीढ़ी को केवल विरोध करना सिखाना चाहता है, या विरोध की भाषा भी।

नामत्सो: तिब्बत की 'स्वर्गीय झील', जहां प्रकृति, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम

● ओमप्रकाश सिंह

तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में ल्हासा से लगभग 240 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम स्थित नामत्सो झील केवल एक प्राकृतिक जलाशय नहीं बल्कि तिब्बती संस्कृति, बौद्ध आस्था और वैज्ञानिक शोध का महत्वपूर्ण केंद्र है। तिब्बती भाषा में 'नाम त्सो' कहलाने वाली इस झील का अर्थ 'स्वर्गीय झील' है। इसे तिब्बत की सबसे पवित्र झीलों में गिना जाता है और हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहां आध्यात्मिक साधना की तीर्थयात्रा के लिए पहुंचते हैं।

समुद्र तल से करीब 4,718 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नामत्सो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित बड़ी खारे पानी की झीलों में शामिल है। लगभग 1,920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह झील करीब 70 किलोमीटर लंबी और 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 125 मीटर है। इसकी अत्यधिक शुद्ध रूप से न्येनचेन तांग्ला झील को मुख्य रूप से न्येनचेन तांग्ला पर्वतमाला से आने वाले हिमनदों के पिघले



पानी और मौसमी जलधाराओं से जल मिलता है। नामत्सो का प्राकृतिक सौंदर्य इसे एशिया के सबसे आकर्षक स्थलों में स्थान दिलाता है। नीले जल, बर्फ से ढंके पर्वत, विस्तृत घास के मैदान और गर्मियों में खिलने वाले जंगली फूल यहां की पहचान हैं। सर्दियों में पूरी झील बर्फ की मोटी चादर से ढंके जाती है।

कठोर जलवायु के बावजूद यह क्षेत्र जैव वि

बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने किया प्रदर्शन

आशुतोष गौतम, हरियाणा मेल

करनाल। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजीव गांधी विद्युत सदन सेक्टर 12 करनाल सर्कल में मीटिंग करने के बाद जिला सचिवालय तक कर्मचारी नारेबाजी करते हुए पहुंचे। यहां तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्षता संयुक्त रूप से युवराज राठौर हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन, महावीर सिंह हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन, विशाल बनवाला सर्कल सचिव ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन ने की। मीटिंग का संचालन गुरमीत सैनी सर्कल सचिव एचएसईबी वर्कर यूनियन और विशाल बनवाला सर्कल सचिव एचएपीसी वर्कर यूनियन ने किया। मीटिंग को मुख्य रूप से राजेंद्र राणा महासचिव ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन और देवेंद्र शर्मा चेयरमैन हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने संबोधित किया। यूनियन नेताओं ने हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की प्रस्तावित योजना, गुरुग्राम और नूंह में निजी बिजली वितरण



लाइसेंस तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रह करने की मांग की। उनका कहना है कि कृषि फीडों की व्यवस्था पहले से अलग है, इसलिए नई कंपनी बनाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से अपनी न्यायोचित मांगों की अनदेखी से परेशान हैं। कई दौर की बातचीत और ज्ञापनों के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी कारण सर्वसम्मति से 11, 12 और 13 अगस्त को प्रदेशभर में तीन दिवसीय पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही चेतावनी

दी गई कि यदि सरकार एग्री डिस्कॉम गठन की अधिसूचना जारी करती है तो यही ज्ञापन अनिश्चितकालीन हड़ताल का अग्रिम नोटिस माना जाएगा। इस अवसर पर सहायक अभियंता सुभाष पन्नु, गौरव शर्मा, वीरेंद्र सिंह, दीपक गर्ग, कार्यकारी अभियंता रवि काजल, राकेश संधू, विकास कुमार, रमेश घरोड़ा, मलकीत सिंह, सीताराम, राजकुमार चौधरी, रविंद्र मान, सुरेंद्र रेड्डू, संजील, नरेंद्र पहल, राजीव राठी, सुरेंद्र कंबोज, जोगिंदर सिंह, कैलाश, युवराज, सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुशील गुर्जर, जिला सचिव सेवाराम और पूर्व राज्य उपप्रधान एनपी सिंह चौहान सहित सैकड़ों बिजली कर्मचारी मौजूद रहे।

शशिपाल से अस्पताल में मिले मंत्री विज

हरियाणा मेल ब्यूरो

करनाल। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज हरियाणा के पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता से एक निजी अस्पताल में मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। शशिपाल मेहता लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे। उन्होंने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की प्रार्थना की।

मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मेरा पिछले 50 वर्ष पुराना साथी है। इस मौके पर मंत्री अनिल विज ने बताया कि पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता ने मुख्यमंत्री बंसी लाल के शासनकाल में प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शशिपाल मेहता एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं व हर परिवार के सुख-दुख में शामिल होते हैं। इस मौके पर मंत्री अनिल विज ने शशिपाल मेहता के सुपुत्र एवं पार्षद संजीव मेहता को



हौसला दिया। मुलाकात के दौरान मंत्री अनिल विज ने डॉक्टरों से उनके उपचार और स्वास्थ्य सुधार के संबंध में जानकारी ली। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है, काफी कवर हो चुका है।

मंत्री ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों की भावनाओं की कद्र करते हैं और उनकी अधिकतर

मांगों को स्वीकार किया। उन्होंने जंतर-मंतर पर चले धरने को लेकर रात को 12 बजे भी अपना संदेश साझा किया। लेकिन विपक्ष के लोगों ने युवाओं को भड़काने की पूरी कोशिश की परंतु युवा बहकावे में नहीं आए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन होते रहते हैं। परंतु प्रदर्शन मर्यादा हीन नहीं होना चाहिए।

हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश को मिला सृजन श्री सम्मान

हरियाणा मेल ब्यूरो

कुरुक्षेत्र। धर्मनगरी की संगीत और कला क्षेत्र में अग्रणी संस्था सृजन द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने शिरकत की। समारोह के दौरान कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में, हरियाणा कला परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सृजन श्री सम्मान से नवाजा गया। मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी की उपस्थिति में संस्था के पदाधिकारी डा. योगेश्वर जोशी ने उन्हें यह सम्मान भेंट किया।

सम्मान ग्रहण करने के बाद दशकों और कला प्रेमियों को संबोधित करते हुए हरियाणा कला



परिषद के उपाध्यक्ष महेश जोशी ने संस्था सृजन का आभार व्यक्त किया। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कला और संगीत की त्रिवेणी बहाने में सृजन संस्था का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा, यह सम्मान केवल मेरा नहीं, बल्कि हरियाणा की उस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन सभी जमीनी कलाकारों का सम्मान है जो दिन-रात कला को जीवित रखने में जुटे हैं। हरियाणा कला परिषद प्रदेश के हर कोने में कला और संस्कृति के संवर्धन तथा कलाकारों के कल्याण व संरक्षण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आगे भी यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा।

कोई तंग या परेशान करे तो डीएलएसए को करवाएं अवगत

कानून से ऊपर कोई नहीं: दिनेश कुमार मित्तल

हरिदास, हरियाणा मेल

कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि किसी दफ्तर, समाज या अन्य स्थान पर किसी को कोई तंग, परेशान करे, या किसी प्रकार की समस्या हो तो इस बारे में डीएलएसए को सूचित करें। पीड़ित, परेशान को न्याय दिलवाया जाएगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। नागरिकों को उनके अधिकारियों और डीएलएसए द्वारा इन कानूनों के बारे में लगातार जागरूक किया जाता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन दिनेश कुमार मित्तल बुधवार को डीएलएसए द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मथाना में आयोजित मेगा लीगल सर्विस कैंप एवं रक्तदान शिविर



में बोल रहे थे। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन दिनेश कुमार मित्तल ने विद्यालय के प्रांगण में पौधा रोपित किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की।

डीएलएसए के साथ सर्व समाज कल्याण संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर

का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएलएसए चेयरमैन दिनेश कुमार मित्तल ने कहा कि हर वर्ष डीएलएसए द्वारा मेगा कैंप का आयोजन किया जाता है। इन कैैंपों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है।

इसके साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को

नागरिकों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों, जरूरतमंद लोगों, बुजुर्गों, स्कूली विद्यार्थियों सहित सभी वर्गों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं बनाकर लागू की जाती हैं। नागरिकों को उन योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने और उनका लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जाता है।

यदि छात्राओं को कोई परेशान करता है तो वो इस बारे में अपने परिजनों, स्कूल के अध्यापकों को बताएं। यदि फिर भी परेशानी हो तो डीएलएसए को बताकर उसका समाधान किया जा सकता है।

डीएलएसए में भी बच्चों के लिए विशेष अधिकार बनाए हुए हैं। उन्होंने परिजनों से आह्वान किया कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें।

सरकार का प्रयास हर शिकायतकर्ता की समस्या का हो समाधान: श्याम सिंह राणा

हरियाणा मेल ब्यूरो

करनाल। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बुधवार को पंचायत भवन के सभागार में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 13 परिवारों में से 7 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया तथा शेष 6 परिवारों की पुनः जांच उच्च अधिकारियों को सौंपी गई।

बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने डीआरपी एनक्लेव कॉलोनी सेक्टर-36 के एनक्लेव रेंजिडेंट्स एवं समस्त कॉलोनी वासियों की शिकायत का मामला कोर्ट में विचारार्थन है। इस मामले पर लीगल एडवाइज ली जाएगी और कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोर्परेटिव सोसायटी द्वारा प्लाट आवंटन मामले में न्यू डीसी कॉलोनी वासी उषा रानी की शिकायत पर मंत्री ने मुख्यालय



से जवाब आने के बाद डीसी द्वारा दोबारा जांच करवाई जाएगी।

नई शिकायतों में संजय निवासी गांव गंगटहड़ी के बेटे के साथ की गई मारपीट के मामले पर मंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि शेष अपराधियों को जल्द पकड़ा जाए व शिकायतकर्ता को कार्रवाई से संतुष्ट किया जाए। कैथल निवासी साहिल सिंगला द्वारा गिरिराज इंडस्ट्रीज मंजूरा द्वारा वेतन न मिलने की शिकायत पर मंत्री ने एडीसी, डीएसपी, लेबर इंस्पेक्टर व समिति के सदस्य द्वारा कमेट्री गठित कर जांच करने के निर्देश दिए। करनाल सेक्टर 7 निवासी विजय कुमार के प्लॉट से नगर

निगम द्वारा सड़क निकालने के मामले में मंत्री ने नगर निगम के संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में तहसीलदार सेल व तहसीलदार की कमेट्री द्वारा जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सेक्टर 9 निवासी कर्मसिंह द्वारा सेक्टर 43 कमशियल, 43 ए व 43 बी इंडस्ट्रियल करनाल का प्लान लागू करने बारे सूचना जारी न करने और सेक्टर 43ए में जीटी रोड एनएच 44 से अंसल टाउनशिप तक डबल लेन सड़क बनाए जाने की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि गेट बंद करने और अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ब्रजेश पाठक ने लगाई हाजिरी बाबा से देश प्रदेश में जनकल्याण की कामना की



हरियाणा मेल, एजेंसी

वाराणसी। गुरू पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। मंदिर के गर्भगृह में बाबा के पावन ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के बाद उपमुख्यमंत्री ने विधि विधान से दर्शन पूजन किया। उपमुख्यमंत्री ने बाबा से देश -प्रदेश में शांति, सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की।

दर्शन-पूजन के बाद मंदिर के

गेट नंबर चार के पास पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सावन माह के शुभारंभ को लेकर जिला और मंदिर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सावन में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।

श्री शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा 34वें कांवड़ सेवा शिविर का भट्टी पूजन से हुआ शुभारंभ

श्री दुःखभंजन महादेव मंदिर में शुरू हुआ कांवड़ शिविर

सोनिका वधवा, हरियाणा मेल

कुरुक्षेत्र। श्री शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के उपलक्ष्य में 34वाँ कांवड़ सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज दुःखभंजन महादेव मंदिर में भट्टी पूजन के साथ इस शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संरक्षक दर्शन गुरी, चेयरमैन डॉ. एम.के. मोदगिल, प्रधान एम.एल. खुरार, उपप्रधान अरवनी अरोड़ा बिट्टू, महासचिव संदीप मरवाहा, कोषाध्यक्ष वेद प्रोवर, सदस्य एस.के. मिश्री, एम.एल. सचदेवा, शशि कपूर, राजकुमार, प्रीतम सुधा, कुलवंत सिंह भट्टी आदि मौजूद रहे।

सभी ने कांवड़ शिविर के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 28 जुलाई से 11 अगस्त तक दुःखभंजन महादेव मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में कांवड़ियों के ठहरने, खाने पीने, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को पूर्ण भंडारे के भी आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 में शिव शक्ति सेवा मंडल द्वारा कांवड़ सेवा शिविर की शुरुआत की गई थी। तब से ये सेवा कार्य लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि सावन माह में प्रतिदिन लगभग 300 कांवड़िए शिविर में शामिल होते हैं। पूरे सावन माह में लगभग 3000 से अधिक कांवड़िये इस शिविर में शामिल होते हैं। मंदिर परिसर में प्रतिदिन 24 घंटे अटूट भंडारा जारी रहेगा। उन्होंने सभी शिव भक्त कांवड़ियों से आह्वान

किया कि सभी नशों से दूर रहे। शिव नाम का जाप करते हुए अपनी कांवड़ यात्रा को पूर्ण करें। मंदिर के चैयरमैन एम.के. मोदगिल ने बताया कि यह सेवा शिविर वीरवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। हालांकि, 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। एम.के. मोदगिल ने कहा कि शिव शक्ति सेवा मंडल की स्थापना वर्ष 1992 में समाज सेवा और धर्म के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। मंडल द्वारा समय-समय पर रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, निशुल्क आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता, निर्धन बच्चों की मदद तथा लावारिस एवं असहाय लोगों के अंतिम संस्कार जैसी अनेक सामाजिक सेवाएं लगातार की जा रही हैं।

महादेव के नाम का करें नशा, कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार के नशे से रहें दूर

हरियाणा मेल ब्यूरो

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के स्नेहित सरोवर पर स्थित श्री दुखभंजन महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित 34वें नशा मुक्त कांवड़ सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। मंदिर के चैयरमैन एम.के. मोदगिल ने बताया कि यह सेवा शिविर वीरवार से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। हालांकि, 11 अगस्त को महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे।

एम.के. मोदगिल ने कहा कि शिव शक्ति सेवा मंडल की स्थापना वर्ष 1992 में समाज सेवा और धर्म के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। मंडल द्वारा समय-समय पर रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, निशुल्क आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता, निर्धन बच्चों की मदद तथा लावारिस एवं असहाय लोगों के अंतिम संस्कार जैसी अनेक सामाजिक सेवाएं लगातार की जा रही हैं।



उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। यदि कोई नशा करना है तो भगवान शिव के नाम का करें, ॐ नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और यात्रा भी सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। मोदगिल ने बताया कि शिविर में कांवड़ियों के लिए तीनों समय निशुल्क भोजन, ठहरने, विश्राम, पेयजल, चिकित्सा सहायता, पैरों में मेहंदी लगाने तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

आरटीआई का जवाब न देने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जनसूचना अधिकारी तलब



हरियाणा मेल, एजेंसी

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में आरटीआई आवेदन पर समय से सूचना उपलब्ध न कराने पर कड़ा रुख अपनाया है और जनसूचना अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी को हाजिर होने का निर्देश दिया और पूछा कि 2026 में कितनी अर्जी आई,और कितने का निस्तारण किया गया और कितनी विचाराधीन है। कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने छात्रा रागिनी सिंह की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका का कहना था कि उसने उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।याचि की ओर से अधिकवा अजीत सिंह और हिमांशु सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रभावी बहस की। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2026 को निर्धारित की है।

खबरें फटाफट

राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में 31 विभूतियों का होगा सम्मान

जयपुर। संस्कृति युवा संस्था की ओर से 31वां राजस्थान गौरव सम्मान समारोह गुरुवार को स्टेशन रोड स्थित होटल आईटीसी राजपूताना शेरटन में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में प्रदेश की विभिन्न क्षेत्रों की 31 लब्ध-प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को 'राजस्थान गौरव' सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष पं. सुरेश मिश्रा ने बताया कि सम्मान समारोह में साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, समाज सेवा, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 31 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र एवं दुग्ध भेंट कर 'राजस्थान गौरव' अलंकरण से विभूषित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे होंगे। कार्यक्रम गुरुवार शाम 4 बजे होटल आईटीसी राजपूताना शेरटन, स्टेशन रोड, जयपुर में आयोजित होगा।

कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का नजदीकी विद्यालयों में होगा विलय: संदीप सिंह

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बुधवार को बताया कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पास के विद्यालयों में विलय किया जाएगा और रिक्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी पाठशालाएं संचालित की जाएंगी। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्री-प्राइमरी कक्षाओं का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार किया जा रहा है। इस दौरान बेसिक शिक्षा मंत्री ने पूर्व सरकार में शिक्षा व्यवस्था की बहाली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नकल अध्यादेश लाकर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया था, जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने रद्द कर दिया। उदाहरण के तौर पर पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट पूर्ववर्ती सरकार के समय में 28,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। संदीप सिंह ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.90 करोड़ हो गया है। स्कूलों में ड्रॉपआउट दर 19% से घटकर 3% हो गई है। पाठ्यक्रम को बेहतर बनाया गया है और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत परिषदीय विद्यालयों में 19 विभिन्न पैरामीटर पर 36% से 97% तक सुधार किया गया है।

सपा कार्यालय में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर बुधवार को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने महाराजा दक्ष प्रजापति के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए आदर्श पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति भारतीय संस्कृति, सभ्यता और सृष्टि निर्माण की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। उनका जीवन श्रम, समर्पण, सामाजिक समरसता और मानव कल्याण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महारूपों के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने तथा सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलाध्याक्ष राकेश मौर्य ने महाराजा दक्ष प्रजापति के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है तथा सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराजा दक्ष प्रजापति के आदर्श आज भी समाज में एकता, सौहार्द और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने उपस्थित लोगों से समतामूलक और मजबूत समाज के निर्माण का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता सुरेंद्र प्रजापति एडवोकेट ने महाराजा दक्ष प्रजापति के जीवन, व्यक्तित्व एवं समाज के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी सामाजिक एकता, श्रम और सम्मान का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इस अवसर पर मोहन प्रजापति, जिलाजीत प्रजापति, दिलीप प्रजापति, अजय प्रजापति, जनादन प्रजापति, मोहित प्रजापति, कैलाश प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष हीरालाल विश्वकर्मा, महेंद्र यादव 'नेपाल', इरशाद मंसूरी, जिला सचिव दीपक विश्वकर्मा, लाल मोहम्मद राईनी, जितेंद्र शर्मा, रवि यादव और नीतू शर्मा सहित अनेक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महाराजा दक्ष प्रजापति को श्रद्धापूर्वक नमन किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया।

हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता: सीएम योगी



हरियाणा मेल, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गुरु पूर्णिमा पर्व संबंधी आनुष्ठानिक कार्यक्रम की व्यस्तता के बावजूद जनता दर्शन का आयोजन किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर व्यक्ति की समस्या का निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान त्वरित और संतुष्टिपरक तरीके से कराना सुनिश्चित किया जाए।

बुधवार सुबह गुरु पूर्णिमा पूजन

के बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। सबको आश्चस्त किया कि किसी को भी चबराते करने की आवश्यकता नहीं है। सबकी समस्या का समाधान सुनिश्चित कराया जाएगा। लोगों के प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक

सीएम ने किया महायोगी गोरखनाथ का विशिष्ट पूजन

गोरखपुर। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुधवार प्रातः काल गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ का नाथपंथ की परंपरा के अनुसार विशिष्ट पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेधनाथ, दादगुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, योगिराज बाबा गंभीरनाथ समेत नाथपंथ के सभी गुरुजन का भी विशिष्ट विधान से पूजा की। गोरक्षपीठाधीश्वर ने भगवान गोरखनाथ और अन्य गुरुजन को श्रद्धा निवेदित कर लोक कल्याण के पथ पर मार्गदर्शन के लिए भावपूर्ण कृतज्ञता व्यक्त की की। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा का विशेष अनुष्ठान प्रातः काल से ही प्रारंभ हो गया और सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान की पूर्णता हुई। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। वैसे तो गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखनाथ मंदिर में होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी तथा नाथपंथ के गुरुजन का दर्शन-पूजन उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा होता है। पर, गुरु पूर्णिमा का अवसर गोरखनाथ मंदिर में विशिष्ट पूजा का होता है। बुधवार को गोरक्षपीठाधीश्वर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गोरखनाथ, मंदिर परिसर में मौजूद सभी देव विग्रहों और नाथपंथ के गुरुओं की प्रतिमाओं के समक्ष विशिष्ट विधान के साथ पूजन किया। आनुष्ठानिक कार्यक्रमों के क्रम में उन्होंने सबसे पहले नाथपंथ के आदिगुरु भगवान गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनकी विशिष्ट पूजा की। वह परिसर में मौजूद सभी देव-विग्रहों के पास पहुंचे और उनका पूजन किया।

मदद की गुहार लेकर पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री योगी ने आश्चस्त किया कि

पैसे की तंगी से किसी का भी इलाज नहीं रुकने दिया जाएगा।

सुलतानपुर में इथेनॉल टैंकर पलटा, 10 किमी सड़क बंद

हरियाणा मेल, एजेंसी

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर के भंदैया स्थित दोमुह्रा-सुलतानपुर रोड पर मंगलवार देर रात इथेनॉल से भरा एक टैंकर पलट गया। यह हादसा छत्तीना गांव के पास आया, जिसमें टैंकर चालक गुरमीत सिंह घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बलरामपुर से इथेनॉल लेकर मिजापुरा जा रहे दो टैंकरों में से एक यूपी 62 एटी 9688, बोती रात लगभग 1 बजे पलट गया। चालक गुरमीत सिंह के अनुसार, सामने से आ रहे ट्रेलर ने साइड भारी, जिससे टैंकर का एक पहिया सड़क किनारे जल जीवन मिशन के लिए खोदी गई पाइपलाइन के गड्ढे में चला गया और टैंकर पलट गया। दूसरा टैंकर (यूपी 61 बीटी 3974) सुरक्षित रहा।

टैंकर पलटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल चालक को बाहर निकाला। चालक ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इथेनॉल ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण, मौके पर तत्काल तीन फायर ब्रिगेड वाहन तैनात किए गए।

सड़क हादसा: ट्रक में घुसी स्कूल वैन, एक छात्र की मौत, 10 बच्चे घायल

हरियाणा मेल, एजेंसी

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के दाहोद मार्ग पर स्थित संत पॉल्स विद्यालय के बच्चों से भरी एक वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। ट्रकर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि वैन में सवार 14 बच्चे घायल हो गए। इनमें से तीन बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें से एक छात्र को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना के वक्त वैन में कुल 15 बच्चे सवार होकर स्कूल जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और भारी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सभी घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया। एक साथ बड़ी



संख्या में घायल बच्चों के अस्पताल पहुंचने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने कई बच्चों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया और कुछ को सीपीआर भी दिया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल में अभिभावकों की भारी भीड़ जमा हो गई और वहां का माहौल गमगीन हो गया। स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत सिंह यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर पर्वत सिंह चुण्डावत, उपखंड अधिकारी सागर कुमार सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली।

आईआईटी कानपुर व आईआईएम इंदौर बनेंगे उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के नॉल्लेज पार्टनर

हर घर शुद्ध जल के संकल्प को नई उड़ान, यूपी में ग्रामीण जलापूर्ति नदियों की सफाई और पुनरुद्धार को बनाएंगे हाईटेक

हरियाणा मेल, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और जलापूर्ति व्यवस्था का आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी कानपुर (ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन) और आईआईएम इंदौर के साथ अहम समझौता किया है। विभागीय ने देश के दोनों प्रतिष्ठित संस्थानों को नॉल्लेज पार्टनर बनाया है।

इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल मॉनिटरिंग और आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति, नदियों की सफाई और पुनरुद्धार को अधिक प्रभावी, पारदर्शी व भरोसेमंद बनाया है। उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक डॉ. राज शेखर ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने से जुड़ी सभी निर्मित, निमाणाधीन व भविष्य की योजनाओं की आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर निगरानी और प्रबंधन आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के लिए भी इसकी जरूरत है। इसी विजन के तहत आईआईटी कानपुर और आईआईएम इंदौर को जल निगम ग्रामीण के साथ जोड़ा जा रहा है। आईआईएम इंदौर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो चुका है।

जल्द ही आईआईटी कानपुर के साथ सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। योगी सरकार का लक्ष्य तकनीक के जरिए पानी की बवादी रोकते हुए हर ग्रामीण परिवार तक गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना है। ऐसे में आईआईटी कानपुर के सहयोग से जल योजनाओं में एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे पाइपलाइन में लीकेज की समय रहते पहचान, जल दबाव और क्लोरीन स्तर की 24 घंटे निगरानी संभव होगी। विशेषज्ञ सौजेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संचालन एवं रख-रखाव को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय भी बताएंगे। वर्तमान योजनाओं का मूल्यांकन कर उसे अधिक सक्षम, किफायती और टिकाऊ बनाने में भी सहयोग देंगे। इसके साथ ही एकीकृत डिजिटल ऐप और डैशबोर्ड के माध्यम से नागरिकों को शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा।

प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में बाघ की अहम भूमिका: विशेषज्ञ

हरियाणा मेल, एजेंसी

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर बुधवार को मानसरोवर स्थित दीप स्मृति ऑडिटोरियम में जयपुर टाइगर फेस्टिवल के तहत 'बाघ संरक्षण-संवाद' आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए बाघ संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और भारतीय संस्कृति में बाघ के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जयपुर टाइगर फेस्टिवल के 8वें संस्करण के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। महोत्सव का आयोजन 18 से 21 दिसंबर 2026 तक जयपुर में होगा।

प्रसिद्ध संगीतकार, गायक एवं वन्यजीव संरक्षक अभिषेक रे ने कहा कि बाघ शक्ति और संयम का अद्भुत संतुलन है। वह प्रकृति से केवल उतना ही लेता है, जितनी आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि संगीत और बाघ संरक्षण उनके बचपन के सपने रहे हैं



तथा जंगल उन्हें नई धुनें रचने की प्रेरणा देता है। इस दौरान उनका रचित 'चीता एथम' भी विद्यार्थियों को सुनाया गया। सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व फील्ड डायरेक्टर सुनयन शर्मा ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण के लिए जंगल और जंगलों के संरक्षण के लिए बाघ आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देना उचित है, लेकिन बाघों को वाहनों से घेरकर दिखाना गलत संदेश देता है। डॉ. राजेश कुमार व्यास ने कहा कि बाघ केवल हिंसक पशु नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और धैर्य का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि कई संस्कृतियों में बाघ की पूजा होती है तथा बैगा जनजाति स्वयं को बाघ का वंशज मानती है।

प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध: सूर्यप्रताप शाही

किसान अनावश्यक रूप से उर्वरकों का न करें अग्रिम भंडारण

हरियाणा मेल, एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान सरकार की प्राथमिकता में है, इसलिए हम उन्हें बीज से लेकर बाजार तक हर सुविधा समय पर उपलब्ध करा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। अनावश्यक रूप से किसान उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें।

बुधवार को लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश में यूरिया 14.52 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 4.81 लाख मी.टन व एनपीके 4.91 मी.टन उपलब्ध



है। इसके अलावा एसएसपी 3.47 मीट्रिक टन, एमओपी 1.11 मीट्रिक टन कुल मिलाकर 28.82 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्रदेश में उपलब्ध है। प्रदेश में एक अप्रैल से 27 जुलाई तक उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण के तुलनात्मक विवरण के अनुसार, 2026 में यूरिया की उपलब्धता 31.55 लाख मीट्रिक टन रही। डीएपी की उपलब्धता 7.11 लाख मीट्रिक टन रही। एसएसपी की उपलब्धता 4.72 लाख मीट्रिक टन रही तथा वितरण 2025 में

पेड़ से लटकते मिले दंपती के शव, छह माह पहले की थी कोर्ट मैरिज

हरियाणा मेल, एजेंसी

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के जिंदा छपरा गांव में बुधवार दोपहर एक युवक और युवती के शव गांव के बाहर लीची के पेड़ से लटकते मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में दोनों की पहचान नवविवाहित दंपती के रूप में हुई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

जिंदा छपरा निवासी रितेश कुमार (22) और उसकी पत्नी पूजा शर्मा (21) के रूप में की है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने लगभग छह माह पूर्व कोर्ट मैरिज की थी और इसके बाद जिंदा छपरा गांव में साथ रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों की भी मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए घटनास्थल की आवश्यक जांच की और साक्ष्य जुटाए।

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। लेकिन पुलिस किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है।

श्रावण मास गुरुवार से श्रीगणेश, अयोध्या पांच जोन, २1 सेक्टर में विभाजित

अयोध्या में कांवड़ यात्रा के लिए अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था

कांवड़ यात्रा को लेकर अयोध्या में पुलिस, पीएस और एसडीआरएफ की व्यापक तैनाती

श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि, व्युआरटी से लेकर यातायात व्यवस्था तक पूरी तैयारी

बाहरी जिलों का पुलिस बल भी मोर्चे पर, श्रावण मेले के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू

हरियाणा मेल, एजेंसी

अयोध्या। श्रावण मास के कांवड़ मेला और झूला मेला के दौरान अयोध्या में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई



है। धार्मिक आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस प्रशासन ने बहुस्तरीय सुरक्षा योजना लागू की है। अयोध्याधाम और नगर क्षेत्र को पांच जोन तथा 21 सेक्टर में विभाजित कर दो पालियों में नागरिक पुलिस और यातायात पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। इस वर्ष श्रावण मास 30 जुलाई (श्रावण कृष्ण पक्ष) से शुरू होकर 28 अगस्त (रक्षाबंधन) तक चलेगा। मेले के दौरान प्रमुख पर्वों का कैलेंडर भी जारी किया गया है। आस्था के

इस महापर्व पर सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार किया गया है। एसपी सिटी अयोध्या चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि शासन के निदेशानुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को गंवावामी तुलसीदास जयंती, 23 अगस्त को एवं पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः सरयू स्नान के साथ मंदिरों में पांच दिवसीय झूलोत्सव का आरंभ और 24 अगस्त को चतुर्थ सोमवार मनाया जाएगा। 26 अगस्त को श्रावण मास की यशोदशी और शिवरात्रि प्रदेो पर नागेश्वरनाथ व अन्य शिवालयों में भारी भीड़ की संभावना है।

15 अगस्त से श्रावण झूला मेला का शुभारंभ

30 जुलाई को श्रावण मास का आरंभ होगा। तीन अगस्त को प्रथम सोमवार, 10 अगस्त को द्वितीय सोमवार और 11 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि मनाई जाएगी। 15 अगस्त से श्रावण झूला मेला का शुभारंभ होगा, जिसमें मणिपर्वत मेला और झूलोत्सव शामिल हैं। 17 अगस्त को तृतीय सोमवार एवं नागपंचमी के अवसर पर लक्ष्मण मंदिर में दर्शन, स्नान और पूजन का विशेष आयोजन होगा। 19 अगस्त को गोस्वामी तुलसीदास जयंती, 23 अगस्त को एवं पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः सरयू स्नान के साथ मंदिरों में पांच दिवसीय झूलोत्सव का आरंभ और 24 अगस्त को चतुर्थ सोमवार मनाया जाएगा। 26 अगस्त को श्रावण मास की यशोदशी और शिवरात्रि प्रदेो पर नागेश्वरनाथ व अन्य शिवालयों में भारी भीड़ की संभावना है।

व्यापार, निवेश, सेवाओं को आसान बनाने और अनावश्यक नियमों को हटाने का निर्देश



बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद व मनजिंदर सिंह सिरसा भी हुए शामिल

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संघु ने व्यापार, निवेश और नागरिक-अनुकूल सेवाओं को आसान बनाने के लिए सभी विभागों को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ़ लिविंग' के विजन के अनुरूप दिल्ली में डीरिगुलेशन (विनियमन में ढील)

दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 'ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस' (व्यापार में आसानी) और 'ईज ऑफ़ लिविंग' (जीवन-यापन में आसानी) के विजन के अनुरूप सभी विभागों को उन सुधारों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है जिनसे प्रक्रियाएं सरल हों, निवेश को बढ़ावा मिले, रोजगार के अवसर पैदा हों और बेहतर, तेज तथा नागरिक-अनुकूल सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पारदर्शी, कुशल और जन-केंद्रित शासन-व्यवस्था के माध्यम से 'विकसित दिल्ली' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

को कम करने और शासन-व्यवस्था को सरल बनाने के सुधारों की प्रगति का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में किए दर्शन-पूजन



हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुधवार को मंदिर मार्ग स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने भगवान के समक्ष राष्ट्र की प्रगति, दिल्ली के सर्वांगीण विकास तथा समाज में शांति, सद्भाव और समरसता की प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर संत-महात्माओं एवं गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। गुरु केवल ज्ञान प्रदान करने वाले शिक्षक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले पथप्रदर्शक होते

हैं। गुरु ही व्यक्ति के भीतर ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और सेवा की भावना का संचार करते हैं तथा समाज और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। गुरु पूर्णिमा भारतीय संस्कृति की उन महान परंपराओं का पर्व है, जो हमें अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। हमारे ऋषि-मुनियों और गुरु परंपरा ने भारत को ज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति की ऐसी अमूल्य धरोहर दी है, जिसने विश्व को सदैव प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हमें अपने जीवन में सत्य, सेवा, अनुशासन, नैतिकता और सदाचार के मूल्यों को अपनाने का भी संदेश देता है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने गुरुजनों के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें।

सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए

मुख्यमंत्री का जताया आभार

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज और सांसद कमलजीत सहरावत ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया।

समाज की दो महिलाओं संतोष देवी एवं सोनिया के साथ दिल्ली की दो महिला लोकसभा सांसदों कमलजीत सहरावत एवं बांसुरी स्वराज ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू करने पर उनका आभार प्रकट किया। संतोष देवी लापरवाह नगर में खाने की रेहड़ी लगाती हैं और सोनिया घरेलू कार्य सहायक के रूप में कार्यरत हैं। कमलजीत सहरावत ने वार्ता में कहा कि दिल्ली का दुर्भाग्य रहा है कि 2014 -2025 तक एक ऐसी सरकार यहां रही जिसने अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सर्वोपरि रखा, चाहे उसके लिए दिल्ली की जनता केन्द्र सरकार की योजनाओं



से अछूती क्यों ना रह जाये।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केन्द्र सरकार की किसी भी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया और अपनी ओर से किसी भी तरह की योजनाओं की पहल नहीं की। जो योजनाएं वे लेकर भी आए वह सिर्फ प्रष्टाचार का माध्यम बरनीं।

कमलजीत सहरावत ने कहा कि 2025 में जब रेखा गुप्ता की सरकार बनी तो उन्होंने जो केन्द्रीय योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं की गई थीं उन्हें लागू किया और साथ ही अब अपनी नई योजनाओं के माध्यम से दिल्लीवालों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मात्र 16 महीने की सरकार ने कई योजनाएं दी और अब दिल्ली लक्ष्मी योजना लागू कर दिल्ली की महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा

गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को ग्राउंड पर चरितार्थ करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट केवल भाजपा का नारा ही नहीं है बल्कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने इसको चरितार्थ करने का काम किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या फिर जन धन योजना हो। 50 फीसदी से ज्यादा बैंक एकाउंट महिलाओं के ही खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय मजबूती दी तो उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें समाजिक न्याय दिया। स्वराज ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो अभियान चलाया उसमें दिल्ली पीछे रह रही थी क्योंकि दिल्ली में तत्कालीन आप-दा की सरकार ने राजनीति द्वेष के कारण उन्हें लागू करने से रोक दिया था।

खबरें फटाफट

कावड़ यात्रा को लेकर तैनात होंगे ढाई हजार पुलिस कर्मी

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने कावड़ यात्रा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया है। कावड़ यात्रा के दौरान यहां के विभिन्न मार्गों और शिवालय पर ढाई हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कावड़ मार्ग पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि श्रावण मह शुक्र होने वाला है। नोएडा और एनसीआर के विभिन्न जगहों से लोग जल लेने के लिए हरिद्वार जाएंगे तथा जल लेकर अपने-अपने गंतव्य तक जाएंगे। जनपद गौतम बुद्ध नगर में कावड़ यात्रा के आठ प्रमुख मार्ग हैं। यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी मार्गों और शिवालय पर पुलिस तैनात की गई है। सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सभी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंटरनेट डिपार्टमेंट कनेक्टि गठित की गई है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, नेशनल हाइवे,स्टेट हाइवे के साथ बैठक की गई है। इन मार्गों को ठीक करवाया गया है। उन्होंने बताया की कावड़ मार्ग पर पुलिस तैनाती की पुख्ता व्यवस्था की गई है। करीब ढाई हजार पुलिसकर्मी कावड़ मार्ग और विभिन्न शिवालय पर तैनात रहेंगे। डीजे संचालकों को भी आदेशित किया गया कि उनको साउंड टाइम मानक के अनुसार ही रखना है। उन्होंने बताया कि कावड़ मार्ग पर मार्क ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

सीवेज प्लांट हादसे पर एनएचआरसी ने लिया सज़ान, दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) की एक आवासीय सोसाइटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जहरीली गैस से दो लोगों की मौत के मामले पर स्वतः संचालन लिया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा कि यह गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। आयोग ने कहा कि रिपोर्ट में जांच की स्थिति और मृतकों के परिजनों को दी गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिली कि 26 जुलाई को सफाईकर्मी टैंक की सफाई के लिए अंदर गया और बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड भी अंदर गया लेकिन वह भी बेहोश हो गया। दोनों की पुलिस और दमकलकर्मियों ने बाहर निकाला और अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

बेखौफ बदमाशों ने कई लोगों से की लूटपाट

नोएडा। नोएडा के विभिन्न जगहों पर बेखौफ बदमाशों ने आधा दर्जन लोगों के साथ लूटपाट की। घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना सेक्टर 63 के प्रभारी निरीक्षक अमित काकरान ने बताया की बीती रात को साविक पुत्र हरमोत रैड्डी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सेक्टर 63 के एच- ब्लॉक में स्थित एक कंपनी में वह काम करते हैं। पीड़ित के अनुसार वह कंपनी से काम करके पैदल घर के लिए जा रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया तथा उसने उनका मोबाइल फोन लूट लिया। थाना सेक्टर 20 के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया की बीती रात को आलोक कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह सेक्टर 31 के मंगल बाजार के पास से शराब की दुकान की तरफ जा रहे थे। वह फोन पर बात कर रहे थे, तभी ठेके के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उनका फोन छीनकर भाग गया। थाना प्रभारी ने बताया कि बीती रात को कुमारी टीया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह सेक्टर 19 में रहती हैं। पीड़िता के अनुसार वह सेक्टर 27 मार्केट में गई थी, तभी बाइक सवार दो बदमाशों ने उनका आईफोन उठके हाथ से छीन लिया। थाना सेक्टर 24 के प्रभारी निरीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि बीती रात को प्रियांशी बरयानी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह विश्वकर्मा रोड सेक्टर 52 के पास से उबर ऑटो में सवार होकर अपने एक दोस्त के साथ घर जा रही थी। जैसे ही वह यूटर्न के पास पहुंची दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनका मोबाई आईफोन लूट लिया। थाना फेस- वन के प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बीती रात को अमन पांडे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह हरौला गांव के पास से जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आते दो बदमाशों ने उनका मोबाइल फोन लूट लिया। थाना बिसरख के प्रभारी निरीक्षक सुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात को आकाश राय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह गौर सिटी -7 एवेन्यू में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार राधा कृष्ण मंदिर के पास से वह पैदल जा रहे थे, तभी बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से लगभग दो तोले वजन की सोने की चेन लूट लिया।

यमुना पुनर्जीवन के लिए लगभग 4,500 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड ने लगभग 4,500 करोड़ की यमुना पुनर्जीवन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में 15 नए विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (डीएसटीपीएस), सीवर नेटवर्क का विस्तार, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का उन्नयन, स्लज प्रबंधन सुविधाओं का विकास, ड्रोन का इन-सिट्ट ट्रीटमेंट तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।

इन मंजूरीयों के साथ दिल्ली जल बोर्ड अब कुल 28 विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों पर कार्य करेगा, जिनमें पहले स्वीकृत 13 डीएसटीपीएस तथा अब स्वीकृत 15 नए डीएसटीपीएस शामिल हैं। यह दिल्ली के सीवेज शोधाग ढांचे के विस्तार की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है।

दिल्ली जल बोर्ड की 179वीं बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए



दिल्ली के जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार ने समस्या की जड़ पर काम करते हुए एक व्यापक एवं अवसरचक्रा आधारित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 1,000 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) सीवेज उत्पन्न होता है। जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, तब राजधानी की कुल सीवेज शोधन क्षमता केवल 749 एमजीडी थी, जिससे उपचार क्षमता और सीवेज उत्पादन के बीच बड़ा अंतर था। सरकार

आआपा ने आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल रखने की मांग की

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) ने आगामी 7 से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल का प्रावधान नहीं रखने पर सवाल खड़ा किया है। आआपा के बुगड़ी से विधायक संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष से अपील करते हुए कहा कि बिना प्रश्नकाल के सदन को आने-जाने वाले लोगों को डायवर्जन पॉइंट पर पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। कांवड़ यात्रा के सुरक्षित संचालन और यातायात व्यवस्था को लेकर मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ और बुलंदशहर के वरिष्ठ अधिकारियों को अंतरराज्यीय समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई है। पुलिस

उपपुक्त यातायात त्रिगुण बिसेस ने बताया कि बैठक में तब हुआ कि तीनों जनपदों के अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। गोष्ठी में निर्णय लिया गया कि मुख्य डायवर्जन पॉइंट्स पर सैफ्टिक बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं और वाहन चालकों को अस्ुविधा न हो।



मतलब क्या है? संजीव झा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए थे, उन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी 650 करोड़ रुपये का घोटाळा सामने आया है, क्या सरकार इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है कि लोगों के सामने यह जानकारी न आए। संजीव झा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा ही एक ऐसी जगह है, बुलाएगी। लगातार यह दूसरा सत्र है, जिसमें प्रश्न काल नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज 29 जुलाई है और 7 अगस्त से सत्र शुरू करना है। सामान्यतः अगर प्रश्न काल रखा जाता है, तो 15 दिन का अंतर रहता है ताकि प्रश्न लगाए जा सकें, उनके जवाब आए और फिर उन्हें विधानसभा पटल पर रखा जाए। तो अगर प्रश्न काल नहीं रखा जा रहा है, तो फिर इस सत्र का

केजरीवाल ने ईश20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

हरियाणा मेल, एजेंसी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इथेनॉल 20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वाहन कंपनियों पर दबाव बनाकर इथेनॉल20 को सुरक्षित बताने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केटीयू जांच ब्यूरो (सीबीआई) व आयकर विभाग को कार्रवाई की धमकी दे रही है।

अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दावा किया कि उन्होंने 29 वाहन निमाता कंपनियों को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या 2023 से पहले बने वाहनों में इथेनॉल20 पेट्रोल का सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि इससे वाहन खराब होता है या माइलज कम होती है तो क्या कंपनियां



इसकी जिम्मेदारी लेंगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कंपनियों से जवाब मांगा तो किसी कंपनी ने लिखित जवाब नहीं दिया, जबकि नौ कंपनियों के अधिकारियों ने फोन पर बातचीत में कथित तौर पर स्वीकार किया कि पुराने वाहनों में इथेनॉल20 के इस्तेमाल से इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान तथा माइलज में गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि देश में 2023 से पहले बनी करीब 30 करोड़ गाड़ियां हैं और सरकार की नीति से ये वाहन प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है,

असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर केजरीवाल ने जताई चिंता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आआपा) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरे देश को असम के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने गुवागरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस संकट की घड़ी में हमें असम के लोगों के साथ खड़े रहना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि असम में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि लोगों को बार-बार ऐसी आपदा का सामना न करना पड़े। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और देशवासियों से असम के बाढ़ प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता करने और राहत कार्यों में सहयोग देने की अपील की। उल्लेखनीय है कि, असम में हालिया बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। शिवसागर, जोरहाट और चराईदेव जैसे ऊपरी असम के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

इससे माइलज कम मिलती है।

केजरीवाल ने कहा कि इथेनॉल20 का दबाव बनाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टाउनशिप तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पेपर लोक मामलों में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग का भी समर्थन किया।

की बुकिंग रद्द कराने और अनुमति लेने का दावा बनाया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि टाउनशिप तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने पेपर लोक मामलों में छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग का भी समर्थन किया।

कावड़ मार्ग पर ट्रक और बोलेरो पिकअप में टक्कर हरिद्वार जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत, पांच घायल

हरियाणा मेल, एजेंसी

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में थाना निवाड़ी क्षेत्र के गंग नहर पटरी पर मंगलवार को मध्य रात्रि को हुए एक सड़क हादसे में बोलोरो पिकअप में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। ये लोग पिकअप में सवार होकर हरिद्वार जा रहे थे, तभी ट्रक ने टक्कर मार दिया।

इस घटना में घायल पांच लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित पक्ष ने कुछ दिन पहले ही पिकअप खरीदा था। ये लोग उसमें सवार होकर हरिद्वार पूजा करने जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि हादसा मंगलवार रात करीब 12:40 बजे निवाड़ी थाना क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर हुआ। जो कांवड़ियों का आरोपी चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है।

जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान रमेश पुत्र छोटेलाल, रतन पुत्र भजनलाल और सरजीत पुत्र खुशीराम के रूप में हुई है। तीनों राजस्थान के अलवर जिले के कलमाग के रहने वाले थे। एसपी के मुताबिक, श्रद्धालु हाल ही में खरीदी गई नई बोलोरो की पूजा कराने और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। तीनों दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी भिड़ंत हो गई। एसपी ने बताया कि शुक्रवार को सवार होकर और बोलोरो दोनों की तेज रफ्तार हादसे की वजह सामने आ रही है। हादसा चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग पर हुआ, जो कांवड़ियों का प्रमुख मार्ग माना जाता है। यह मार्ग गाजियाबाद के मुरादनगर से शुरू होकर मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार तक जाता है। 29 जुलाई की सुबह से इस मार्ग पर भारी वाहनों का डायवर्जन लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही दर रात यह दर्दनाक हादसा हो गया।

2026-27 में 11 और खदानों को बंद करना है, जबकि शेष 15 खदानों में वित्त वर्ष 2027-28 में चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। साइड इंटर कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हरिश दुहान कहते हैं, खदान का बंद होना खनन गतिविधियों का अंत नहीं बल्कि एक नए शुरुआत है। उन्होंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य भूमि पुनर्स्थापन, पर्यावरण संरक्षण और पुनर्विकसित खदान क्षेत्रों को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, आजीविका सृजन तथा स्थानीय समुदायों के उपयोगी संसाधन के रूप में विकसित करना है। हरिश दुहान ने कहा कि कंपनी वर्तमान में 8 खदानों के पुनः उपयोग में लाने की परियोजनाओं पर काम कर रही है, जो कोल इंडिया लिमिटेड की सभी कंपनियों में सबसे अधिक हैं।

मुख्यमंत्री ने पंचकूला में गुप-डी के नव-चयनित कर्मचारियों के लिए आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में किया सम्बोधित

मेहनत, योग्यता और प्रतिभा ही सरकारी नौकरी का आधार: नायब सैनी

सरकारी कर्मचारी गुड गवर्नेंस की डिलीवरी टीम, जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें: मुख्यमंत्री

- हरियाणा में भर्ती व्यवस्था में आया ऐतिहासिक बदलाव, पारदर्शिता से मिल रही हैं नौकरियां: मुख्यमंत्री
- गुप-डी के 3,586 नव-चयनित कर्मचारियों को दी बधाई, 6 युवाओं को सौंपे प्रतीकात्मक नियुक्ति पत्र
- परीक्षा एवं भर्ती की पवित्रता से कोई समझौता नहीं: नायब सैनी

हरियाणा मेल ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश की भर्ती व्यवस्था में व्यापक और ऐतिहासिक सुधार किए हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं के मन में संदेह और निराशा का माहौल था, वहीं आज पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली के चलते युवाओं का विश्वास सरकार पर मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में अब न पचीं चलेगी, न खचीं चलेगी, बल्कि केवल योग्यता, मेहनत और प्रतिभा के आधार पर ही सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री सैनी पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित गुप-डी के नव-चयनित कर्मचारियों के परिचयात्मक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों



नाम सुनते ही सामान्य परिवारों में चिंता का माहौल बन जाता था। नौकरियों पर कुछ खास लोगों, परिवारों और क्षेत्रों का प्रभुत्व माना जाता था। उस समय योग्यता और प्रतिभा को दरकिनार कर पचीं, खचीं, परिवारवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाता था। इस व्यवस्था ने न केवल युवाओं के अवसर छीने, बल्कि उनके परिवारों का विश्वास भी तोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि अब किसी भी युवा का भविष्य किसी सिफारिश या धनबल से तय नहीं होगा, बल्कि उसकी मेहनत और योग्यता ही उसका भविष्य तय करेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब सरकारी नौकरियां किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि प्रदेश के हर कोने के युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। इससे युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ा है। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि वे केवल गुप-डी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सुशासन की डिलीवरी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं, बल्कि जनसेवा का एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

उन्होंने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने हर निर्णय में समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के हित को ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि यह सोच केवल नीति-निमाताओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर सरकारी कर्मचारी के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे कार्यालय में आने वाले हर व्यक्ति की समस्या को धैर्यपूर्वक सुनेंगे,

युवाओं को दुबई और 390 युवाओं को इजराइल भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त जापान, ओमान, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी युवाओं को भेजने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अवैध एजेंटों और डकी रूट जैसी समस्याओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए हैं, जिससे युवाओं का शोषण रोका जा सके।

मुख्यमंत्री ने परीक्षा और भर्ती प्रणाली की पवित्रता को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा प्रश्न है। उन्होंने कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप सामने आने पर केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करवाई और सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि लोक परीक्षा अधिनियम, 2026 के तहत परीक्षा अपराधों में सख्त लोगों के लिए 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट



चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर पर लोगों की समस्याएं सुनते हुए मुख्यमंत्री

संदेश है कि मेहनती छात्रों के साथ किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की पारदर्शिता और निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मानव संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री पीसी मीणा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री का

आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके विचार सभी कर्मचारियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम केवल नियुक्ति पत्र वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रणाली पर जनता के विश्वास का प्रतीक है।

इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारीगण और अधिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने न केवल नव-नियुक्त युवाओं में उत्साह का संचार किया, बल्कि प्रदेश में पारदर्शी और निष्पक्ष शासन व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूती से प्रस्तुत किया।

समाचार सार

निजी एयरलाइंस का पायलट 814 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार

गुरुग्राम। सेक्टर-39 क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक निजी एयरलाइंस के पायलट को 814 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार किया। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है। आरोपी की पहचान अरशद अली अज्जू, 33 वर्ष निवासी कोझिकोड केरल के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले तीन साल से पायलट है और नौएडा से पांच लाख रुपये में एमडीएमए लाकर बेचता था। पहले वह खुद नशा करता था, बाद में मुनाफ़े के लिए बेचने लगा। पुलिस ने राजेंद्रा पार्क थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी की है, ताकि स्प्लाइंट नेटवर्क का खुलासा किया जा सके।

हरियाणा विधानसभा के महिला युवा संवाद-2026 में एंजल अहलावत का चयन

चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में 31 जुलाई को आयोजित होने वाले महिला युवा संवाद-2026 के लिए एंजल अहलावत का चयन किया गया है। बहु-स्तरीय चयन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद उन्हें सत्पाक्ष का प्रतिनिधित्व सौंपा गया है। इस मंच पर वह विकासत भारत-2047 के संदर्भ में महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखेंगी। कार्यक्रम में देशभर से चयनित युवा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। एंजल अहलावत छात्र नेतृत्व में भी सक्रिय रही हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जिम्मेदार भूमिकाएं निभाकर अपनी पहचान बना चुकी हैं।

7 निगरानी समितियों का गठन

सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी, कार्रवाई के निर्देश

खुले मैनेहोल और छतों पर रोक के लिए कड़े आदेश, रिपोर्टिंग में देरी बर्दाश्त नहीं

हरियाणा मेल ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री रणबीर गंगवा ने सीवरेज और मैनेहोल से जुड़े कार्यों में होने वाली दुर्घटनाओं और लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए विभागीय



अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सुरक्षा उपायों की अनदेखी के कारण किसी कर्मचारी की जान जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की हिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

मंत्री रणबीर गंगवा ने इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रदेशभर में

निगरानी के लिए सात समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक समिति में मुख्य अभियंता, संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता तथा मंडल के कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) शामिल होंगे। ये समितियां नियमित रूप से फ़ील्ड का निरीक्षण करेंगी, सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगी और अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यालय को भेजेंगी, जिसे तुरंत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण को निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य अभियंताओं को उनके वर्तमान क्षेत्र से अलग सर्कलों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिना सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों और नियमों के अनुसार किए किसी भी कर्मचारी को सीवरेज या मैनेहोल में उतरने की अनुमति न दी जाए। मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में

कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ठेकेदारों और अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट दिखाई दी है। खुले मैनेहोल के कारण भी हादसों की सूचनाएं मिली हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने सभी मैनेहोल को सुरक्षित ढंग से बंद करने और उनकी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने यह भी कहा कि कई मामलों में दुर्घटना के बाद समय पर प्रारंभिक रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय तक नहीं पहुंचती, जो गंभीर लापरवाही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर घटना की जानकारी तुरंत मुख्यालय को भेजना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने दोहराया कि विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय कर ही ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।

सिंहासन डोला तो शिक्षा मंत्री का हुआ इस्तीफा

कौन वो कूर सिंह था जिसने AK-47, पैलेट गन, आँसू गैस के गोले, और लाठीचार्ज में कीले लगाकर देश के नौजवानों पर बरसाने का काम किया

हरियाणा मेल ब्यूरो

चंडीगढ़। कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक मामलों और छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस बर्बरता को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। हुड्डा ने कहा कि जिस परिस्थिति में यह

बिल लाया गया, उससे साफ है कि सरकार का उद्देश्य युवाओं की आवाज दबाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरकार को लगा कि सिंहासन डोल रहा है तब एल्लबजी में बिल लाया गया, इस्तीफा हुआ और तत्परता दिखाने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। उन्होंने तर्ज कसते हुए कहा कि अगर सही मायनों में कानून बनाना था तो प्रावधान होना चाहिए था कि पेपर लीक होने पर सबसे पहले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि देश का छात्र आज सबसे अधिक तनावपूर्ण जीवन जीने को मजबूर है और शिक्षा व्यवस्था एलिमिनेशन सिस्टम बन गई है। हुड्डा ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने युवाओं पर हुई

सख्ती देखी। उन्होंने महाराष्ट्र की छात्रा रिया अहीर का उदाहरण देते हुए कहा कि विरोध करने पर भी छात्रों को परेशान किया गया। विधेयक की आलोचना करते हुए हुड्डा ने कहा कि इसमें नए प्रावधानों के नाम पर केवल कमेंटियां और सजा बढ़ाने की बातें हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही लाखों मामलों लंबित हैं और पेपर लीक मामलों में जांच एजेंसियां समय पर साक्ष्य तक जुटाने में विफल रही हैं। हुड्डा ने कहा कि जेन-जी के युवाओं ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अहिंसक तरीके से अपनी आवाज उठाई और यह सरकार की विफलता तथा छात्रों की जीत का प्रतीक है।



सविदा महिला कर्मचारियों को साल में मिलेंगी १२ कैजुअल लीव

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

हरियाणा मेल, एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने सविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैजुअल लीव (सीएल) की सुविधा बढ़ा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पात्र महिला सविदा कर्मचारियों को अब एक वर्ष में अधिकतम 22 दिन की कैजुअल लीव देने का निर्णय लिया है। इससे पहले यह सुविधा केवल 10 दिन तक सीमित थी। उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार,

पात्र महिला सविदा कर्मचारियों को हर माह एक अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी। यह सुविधा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिला कर्मचारियों पर लागू होगी। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

इस सुविधा का लाभ महिला एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी सहित अन्य सविदा कर्मचारियों को मिलेगा। यह लाभ हरियाणा सरकार की ओर से समय-समय पर जारी नियमों और निर्देशों के अनुसार लागू रहेगा।

महानिदेशक कार्यालय ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के अधिकारियों और जिला व उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को आदेश भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को अनुरोध किया है।

सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों महिला सविदा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। अतिरिक्त अवकाश की सुविधा मिलने से महिला कर्मचारियों को नौकरी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन करने में सहायता मिलेगी। यह निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए बेहतर और सुविधाजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने

अब 11 अगस्त से शुरू होगी डाटा वेरिफिकेशन प्रक्रिया

हरियाणा मेल, एजेंसी

चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षक ट्रांसफर ड्राइव-2026 का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार 11 अगस्त से शिक्षकों के व्यक्तिगत और सेवा संबंधी विवरण के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को संशोधित शेड्यूल के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

विभाग ने बताया कि 23 जुलाई को जारी किए गए पहले कार्यक्रम में बदलाव करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। इसके तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षक एमआईएस पोर्टल पर अपने रिकॉर्ड को अपडेट और सत्यापित करेंगे। शिक्षकों की जांच के लिए अपने विवरण की जांच कर उसे प्रामाणिक करना होगा।

18 और 19 अगस्त को शिक्षकों का स्कोर और कार्यभार विवरण जारी किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक को इसमें आपत्ति होगी तो वह 20 से 24 अगस्त तक ऑनलाइन दावा दर्ज करा सकेगा। जिला स्तरीय समिति 25 से 31 अगस्त तक इन दावों पर विचार करेगी

नया टीचर ट्रांसफर ड्राइव-2026 का शेड्यूल

प्रोफाइल अपडेट व सत्यापन 11 से 17 अगस्त
स्कोर व टैन्डोर प्रकाशित 18 से 19 अगस्त
दावा/आपत्ति दर्ज 20 से 24 अगस्त
जिला समिति का निर्णय 25 से 31 अगस्त

जिला समिति का निर्णय प्रकाशित 01 सितंबर
राज्य समिति में आपत्ति 02 से 04 सितंबर
राज्य समिति का निर्णय 05 से 07 सितंबर
अंतिम स्कोर व टैन्डोर सूची 08 से 09 सितंबर

और 1 सितंबर को निर्णय जारी किए जाएंगे। इसके बाद असंतुष्ट शिक्षक 2 से 4 सितंबर तक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। समिति 5 से 7 सितंबर तक मामलों का निपटारा करेगी। 8 और 9 सितंबर को अंतिम

स्कोर और टैन्डोर सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर स्थानांतरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाग ने बताया कि कपल केस के लिए अंक प्राप्त करने हेतु इंटरटेकिंग का प्रारूप तैयार किया गया है।

क्रियान्वयन

कानून बनाना आसान, लागू करना असली चुनौती: सैलजा

मानसिक स्वास्थ्य कानून के क्रियान्वयन पर हाई कोर्ट की टिप्पणी सरकार की प्रशासनिक विफलता को उजागर करती है

हरियाणा मेल ब्यूरो

चंडीगढ़। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने कहा है कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की सफलता केवल नए कानून बनाने से नहीं, बल्कि उनके ईमानदार और प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के लागू करने में वर्षों



की देरी पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि अदालत की टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि कानून बनाने के बावजूद उसका वास्तविक लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। सैलजा ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का उद्देश्य

कुमारी सैलजा का सरकार पर सीधा हमला

मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सम्मानजनक उपचार उपलब्ध कराना था। यदि आठ वर्षों के बाद भी अदालत को सरकारों से यह पृष्ठना पड़ रहा है कि कानून लागू क्यों नहीं हुआ, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि शासन व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल एक कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य मामलों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 2023 में नारी वंदन अधिनियम पारित किया, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में अपेक्षित प्रगति नजर नहीं आती। इसी तरह लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम)

अधिनियम, 2024 को बड़े दावों के साथ लागू किया गया था, ताकि पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर सख्ती से रोक लगाई जा सके। इसके बावजूद देशभर में पेपर लीक और परीक्षा विवाद लगातार सामने आते रहे हैं, जिससे सरकार की नीयत और कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। सैलजा ने कहा कि यदि इन कानूनों को शुरू से ही सख्ती और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता, तो लाखों विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ता और बार-बार परीक्षा रद्द करने की नौबत नहीं आती। इससे युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा भी कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देना और उसके बाद जिम्मेदारी से पीछे हट जाना सुशासन का उदाहरण नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि

सरकार द्वारा फास्ट-ट्रैक कार्रवाई और त्वरित न्याय के दावे किए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में कई मामलों में न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रियाएं धीमी रहती हैं। ऐसे में अदालतों को हस्तक्षेप कर सरकारों से जवाब मांगना पड़ता है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति है।

अंत में सैलजा ने कहा कि कांग्रेस का मानना ​​है कि कानून जनता के हित और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, न कि केवल प्रचार के लिए। प्रशासनिक प्रक्रियाएं धीमी रहती हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि हर कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, जवाबदेही और समयबद्ध समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके और लोकतंत्र की विश्वसनीयता मजबूत हो।

कहटपंथी सांसद अमृतपाल की रिहाई की मांग पर चंडीगढ़ में आंदोलन

कई घंटे तक चला हंगामा

चंडीगढ़ व पंजाब की सीमा पर पुलिस ने लाठीचार्ज करके रोका, प्रदर्शनकारी वाटर कैनन वैन पर चढ़े

हरियाणा मेल, एजेंसी

चंडीगढ़। देशद्रोह के मामले में असम की डिब्रुगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को वारिस पंजाब दे पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर उन्हें रोक दिया। इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी चंडीगढ़ सीमा में घुसने में सफल रहे, जिन्हें बाद में हिरासत में ले लिया गया।



मोहाली-चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं, जो कई घंटों तक जारी रही। कुछ प्रदर्शनकारी वाटर कैनन वैन पर चढ़ गए और हालात तनावपूर्ण हो गए। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शहर में कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। पार्टी नेता मनप्रदी अयाली ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया, जबकि अमृतपाल के वकील इमान सिंह खारा ने कहा कि एनएसए हटने के बावजूद उन्हें अन्य मामलों में जेल में रखा गया है।